स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

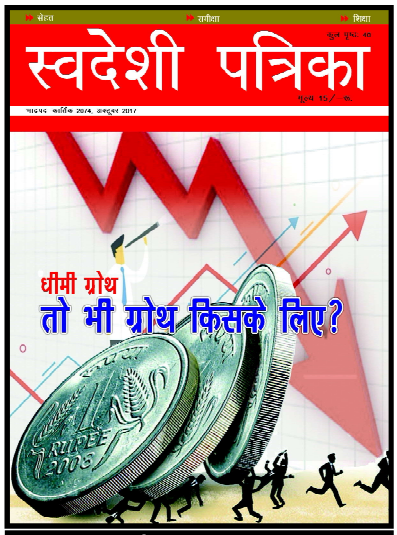

वर्ष–25, अंक–10
अश्विन–कार्तिक 2074, अक्टूबर 2017

संपादक
अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6
ग्रोथ धीमी, तो भी ग्रोथ किसके लिए?
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 संस्कृति
स्वास्थ्यकारी A2 बनाम रोगकारी दूध A1
..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

10 विचार
दुनिया में फैलता चीन का आर्थिक साम्राज्यवाद
..... दुलीचन्द रमन

13 समीक्षा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कैसे करें उपयोग
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

15 कृषि
उद्योगों के विकास के लिए खेती की बलि?
..... देविंदर शर्मा

17 कृषि
लागत घटे, तो खेती बनें उत्तम
..... अरूण तिवारी

19 जीएम फसलें
खतरनाक है जीएम फसलों का प्रसार
..... भारत डोगरा

21 संस्मरण
पं. दीनदयाल उपाध्याय: विचारों की मुंदरी का अनगढ़ नगीना
..... आशीष रावत

23 भाषा
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

26 शिक्षा
उद्योगोन्मुख शिक्षा: राष्ट्रीय विकास का आधार
..... डॉ. रेखा भट्ट

29 सेहत
जैविक आहार – व्यवहार
..... डॉ. विजय वशिष्ठ

32 स्वदेशी गतिविधियां
प्रेस कवरेज: चीन विरोधी अभियान

पाठकनामा

51kyesausrkvksadh500xqukdekbZdS1s\

देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को मालिक और जनप्रतिनिधि (नेता) को सेवक माना गया है। लेकिन हो उल्टा रहा है, तंत्र में मालिक कंगाल (गरीब) और सेवक मालामाल है। आज मान्यता यह हो गई है कि नेतागिरी से अच्छा कोई धंधा नहीं, जो दिन दूनी, रात चौगनी कमाई से सराबोर कर दे। अगर हालात ऐसे बने रहे तो एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगा! है, ना कमाल की बात! जो काम 125 करोड लोग मिलकर नहीं कर सकते वह चंद मुट्ठी भर नेताओं ने कर दिखाया। काश! ऐसी बरकत सभी पर बरस जाए तो क्या कहने, ना कोई भूखा, ना कोई बेघर और ना कोई लाचार, तरबतर में चंहुओर होगा नवउदार।

दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों थोमापिकेती और लुकासॉसेल के एक अध्ययन में सामने आया कि मूल्क में 1 फीसदी जन के पास 22 फीसदी दौलत है। 186 देशों में भारत का गरीबी देशों की सूची में 136 वां स्थान हैं। अपृश्यता में गरीबी, अमीरी और नेतागिरी की खाई देश के अर्थतंत्र को खस्ता बना रही है।

बहरहाल, सियासी दावपेंच से कमाई गई अकूत संपत्ति की चकाचौंध से सारा देश भौचक्का रह गया, जब एक एनजीओ (संगठन) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में तल्ख टिप्पणी करते हुए दो चुनावों के बीच में बढ़ी नेताओं की बेशुमार पूंजी पर गहरा अफसोस जाहिर किया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बेहिसाबी धनपति नेताओं की सूची व रिपोर्ट के साथ पेश करने का निर्देश दिया। गौरतलब रहे कि इस फेहरिस्त में तकरीबन हरेक राजनैतिक दलों के 289 नेता शामिल है। आश्चर्यचकित तथ्य यह है कि 5 साल में नेताओं की 500 गुना कमाई हुई है।

अंततः देश की चिंता से बेफिक्र लुटेरे नेताओं को हायतौबा करने का वक्त आ गया। अन्यथा जिस गति से नेता कमाई कर रहे है, उससे तेजी से नेता लोगों को त्राहिमाम–त्राहिमाम करा देगें।

हेमेन्द्र क्षीरसागर, *बालाघाट, म.प्र.*

*****

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

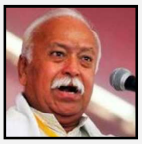

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, आर्थिक स्थिति में द्रुत गति से प्रगति व समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए शासन द्वारा जनधन, मुद्रा, गैस सब्सिडी, बीमा जैसे बड़े निर्णय लिए गये हैं। यह प्रशंसनीय है।

डॉ. मोहन भागवत
प्रमुख, आर.एस.एस.

शौचालय सचमुच में एक इज्जत घर है, खासकर हमारी बहन-बेटियों के लिए और जहां इज्जत घर है, वहां घर की भी इज्जत है... जहां इज्ज़त घर है, वहां गांव की भी इज्ज़त है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

एनपीए की समस्या से निपटने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में काफी गिरावट करनी होगी।

अरूण जेटली
वित्तमंत्री

उत्तर कोरिया के साथ वार्ता करना समय की बर्बादी है। अमरीका को जो करना है, वो करेगा।

डोनाल्ड ट्रंप
राष्ट्रपति, अमरीका

संपादकीय

बिटकॉइन पर प्रभावी प्रतिबंध की जरूरत

दुनिया में अनेक अनोखी मुद्राएं चल रही हैं, जो वास्तविक नहीं हैं, जिनको जारी करने वाली कोई अधिकारिक संस्था अथवा सरकार नहीं होती, फिर भी उस मुद्रा का लेनदेन होता है और कई स्थानों पर उसके द्वारा भुगतान भी किया जाता है। इसे आभासी अथवा वर्चुअल मुद्रा भी कह सकते हैं। इन करैंसियों को क्रिपटो करैंसी कहा जाता है। इनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित मुद्रा है, बिटकॉइन। कहा जाता है कि इसका अन्वेषण एक अनजान कंप्यूटर प्रोग्रामर अथवा प्रोगामरों के एक समूह ने किया। जिसे 'सतोशी नाकामोटो' के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रा के लेनदेन की खास बात यह है कि यह दो लोगों के बीच सीधे तौर पर होती है और उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। इन लेनदेन को नेटवर्क के संकेतो द्वारा सत्यापित किया जाता है और ब्लॉकचैन के नाम से एक सार्वजनिक खाते पर इसको रिकार्ड किया जाता है।

हाल ही में दुनिया भर में कम्प्यूटर अपराधियों द्वारा वैश्विक स्तर पर साइबर हमले किए गए जिससे 150 देशों के 2 लाख से ज्यादा कम्प्यूटर बुरी तरह से प्रभावित हो गए। इस साइबर हमले से जुड़े अपराधियों ने कम्प्यूटर डाटा वापिस देने के लिए जो फिरौती मांगी, उसे सुनकर दुनिया दंग रह गई क्योंकि वह फिरौती बिटकॉइन में मांगी गई थी। सामान्यतौर पर हम कम्प्यूटर की मद्द से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाईन बैंकिंग इत्यादि से आनलाईन लेनदेन करते हैं। यह सभी लेनदेन वैध और भलीभांति रिकार्ड होते हैं, जिसमें लेनदेन करने वालों की जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन बिटकॉइन में किए जा रहे लेनदेन की विशेषता यह है कि इसमें ब्लॉकचैन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस चैन को 'डार्कवैब' पर ब्राउज किया जाता है, जिस कारण उस लेनदेन से जुड़े लोगों का पता लगाना बहुत कठिन होता है। ये लेनदेन अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनको वापिस नहीं किया जा सकता, इसलिए अपराधियों के लिए यह सबसे सुरक्षित लेनदेन का तरीका बन चुका है। टैक्स चोरी हो, हवाला हो, अपराध अथवा आतंकवाद सभी गतिविधियों में बिटकॉइन अपराधियों की पहली पसंद बन चुका है। बिटकॉइन के अपराध में बढ़ते उपयोग ने सुरक्षा एजेंसियों और वित्तीय नियंताओं का जीवन दूभर किया हुआ है। 'मनी लार्न्डिंग' का यह सबसे सुरक्षित तरीका है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन वॉलेट में पैसा डालकर उसे किसी भी टैक्स हैवन में स्थानांतरित कर सकता हैं। बिटकॉइन की यह खासियत है कि इसे कोई व्यवस्था पकड़ नही पा रही। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि बिटकॉइन में पैसा डालना अवैध है। सरकार और आरबीआई द्वारा चेतावनियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं और सरकार द्वारा यह कहे जाने पर कि इसमें पैसा डालना 'मनी लार्डिंग' का अपराध माना जाएगा, के बावजूद भी अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बिटकॉइन नेटवर्क को डाउनलोड किया हुआ है। दुनिया के किसी केंद्रीय बैंक को इसका समर्थन नहीं है और यह किसी भी प्रकार से वैध टैंडर मुद्रा नहीं है क्योंकि इसे किसी बैंक ने जारी नहीं किया। इसी कारण इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। शायद यही बात है कि बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खासतौर पर अपराधियों के बीच। आम लोगों के बीच भी बिटकॉइन के लिए बढ़ते पागलपन के पीछे इसकी लगातार बढ़ती कीमत है। चूंकि मांग और पूर्ति के आधार पर बिटकॉइन की बाजार कीमत तय होती है, इसलिए इसमें उतार–चढ़ाव काफी मात्रा में होते हैं। इसलिए बिटकॉइन का 'क्रेज' सट्टेबाजों में भी खूब रहता है। इसमें निवेश करने वालों में कालाधन रखने वालों की तादाद ज्यादा हैं, क्योंकि वह उनकी सुरक्षित पनाहगार बन चुका है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता इस वजह से भी है कि इसका मूल्य (डालरों में) भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010 में जहां 1000 बिटकॉईन एक पिज्जा के मूल्य के बराबर थे, सितंबर 2017 तक आते–आते एक बिटकॉइन की कीमत 5000 डालर के बराबर पहुंच गई, यानि 3 लाख 20 हजार रूपए प्रति बिटकॉइन। वर्ष 2017 के प्रारंभ में यह 1000 डालर के बराबर ही था। बिटकॉइन धारकों की बढ़ती कमाई के कारण लोगों में बिटकॉइन की ओर पागलपन बढ़ता जा रहा है। स्विट्जरलैंड शायद पहला ऐसा देश बन गया, जहां कुछ स्थानीय निकायों में बिटकॉइन में टैक्स भरा जा सकता है। सभी को मालूम है कि स्विट्जरलैंड के बैंक दुनिया भर के कालेधन के पनाहगार बने हुए हैं।

कंपनियों द्वारा आईपीओ (यानि इनिशियल पब्लिक ऑफर) में तमाम प्रकार के नियमों और कायदों का अनुपालन जरूरी है। लेकिन आजकल कंपनियों ने क्रिपटो करैंसी के माध्यम से पूंजी जुटाने का एक तरीका 'आईसीओ' (यानि इनिशियल कॉईन ऑफर) अपनाना शुरू कर दिया है। इसमें एक कंपनी निश्चित मात्रा में कॉइन जारी करती है और उसे लोग खरीदते हैं। सभी कॉइन बिकने पर बिक्री बंद हो जाती है और इन 'कॉइनों' के धारक उनका जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं। वित्तीय अनुशासन को भंग करती, अपराधियों एवं मनी लॉर्डिंग को बढ़ावा देती इस बिटकॉइन सरीखी क्रिपटो कैरेंसियों का चलन आज दुनिया के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। इससे अर्थव्यवस्थाओं और समाज को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि लोगों की गाढ़ी कमाई इसमें बर्बाद जरूर होती है। समय की मांग है कि जल्द से जल्द इन गैर कानूनी आपराधिक करैंसियों से मानवता को निजात दिलाई जाए। ❑

आवरण कथा

ग्रोथ धीमी, तो भी ग्रोथ किसके लिए?

वर्ष 2017–18 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4 प्रतिषत ही रही, जो 2016–17 की इसी तिमाही में 7.6 प्रतिषत की ग्रोथ से काफी कम है। गौरतलब है कि पिछले तीन सालों में अर्थव्यवस्था में लगातार अच्छे प्रदर्षन के बाद ग्रोथ में यह गिरावट मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय बन रही है। ध्यान से देखा जाए तो यह मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ घटने के कारण हुआ है। पूर्व वित्तमंत्री यषवंत सिन्हा के तीखे बयानों के बाद तो इस विषय ने ज्यादा ही तूल पकड़ लिया है। पिछले साल 2016–17 में नोटबंदी के बाद भी यह ग्रोथ 7.2 प्रतिषत रही थी। सरकार ने इस मंदी से निपटने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। यही नहीं योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष ने भी तमाम पक्षों के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है।

ऐसी खबरें आ रही हैं कि अर्थव्यवस्था को धीमेपन से बाहर करने के लिए राहत और बूस्टर पैकेज देने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि कंपनियों को निवेष करने हेतु ज्यादा पैसा देने और बैंकों को एनपीए से निजात दिलाने हेतु राहत देने की तैयारी चल रही है। सरकार की कोषिष रहेगी कि यह सब राजकोषीय अनुषासन को बनाए रखते हुए किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस काम के लिए पैसा टैक्स के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से जुटाया जाएगा। यानि इसके लिए विनिवेष को भी बढ़ाया जाएगा।

भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1990–91 में 11,535 रूपए ही थी, जो 2016–17 तक बढ़कर 1,15,428 रूपए हो चुकी है। यदि उसमें से कीमत वृद्धि (6.6 गुणा) घटा भी दी जाए तो ध्यान में आता है कि प्रतिव्यक्ति आय 3.4 गुणा बढ़ चुकी है। लेकिन क्या इस अनुपात में लोगों का कल्याण बढ़ा?

– डॉ. अश्वनी महाजन

क्या ये रेडीमेड समाधान हैं सही?

यह पहली बार नहीं है कि मंदी से निपटने के लिए राहत पैकेज दिए जायेंगे। विकसित देषों में तो यह पुराना रिवाज है। 2007–08 की मंदी के बाद अमरीका, यूरोपीय देषों और अन्य विकसित देषों ने इस प्रकार के राहत पैकेज दिए ही थे, भारत ने भी उसी तर्ज पर भारी मात्रा में 'बेल आऊट' पैकेज दिए। नतीजन अमरीकी राष्ट्रपति को सरकारी कर्ज की सीमा को बढ़वाने के लिए अमरीकी कांग्रेस (संसद) के पास गुहार लगानी पड़ी और अब तक अमरीका में सरकारी कर्ज 2007 में जीडीपी के 35.3 प्रतिषत से बढ़ता हुआ, जुलाई 2016 तक जीडीपी के 76.5 प्रतिषत तक पहुंच गया।

उस दौरान भारत सरकार द्वारा बेल आऊट पैकेज के नाम पर टैक्सों में राहत और कंपनियों को रियायतों देने के कारण भारत में राजकोषीय घाटा 2007–08 में जीडीपी के 2.5 प्रतिषत से बढ़ता हुआ 2009–10 में जीडीपी के 6.5 प्रतिषत तक पहुंच गया। इस कारण सरकारी कर्ज भी काफी मात्रा में बढ़ गया। आंतरिक सरकारी कर्ज 2007–08 में 18 लाख करोड़ रूपए से बढ़ता हुआ वर्ष 2010–11 तक 29 लाख करोड़ रूपए हो चुका था। इसके फलस्वरूप देष में महंगाई बढ़ गई और ब्याज दरें भी। अंतोत्गत्वा सट्टेबाजों और कालाबाजारी के चलते बढ़ती महंगाई ने ग्रोथ पर लगाम लगा दी और जीडीपी ग्रोथ

2007–08 में 9.5 प्रतिषत वार्षिक से घटती हुई 2013–14 तक मात्र 4.7 प्रतिषत वार्षिक पर पहुंच गई। दुनिया भर से अर्थषास्त्रियों ने इसे 'मिडिल इन्कम ट्रैप' यानि 'मध्य आय का मकड़जाल' का नाम दे दिया और कहा जाने लगा कि भारत तीन दषकों तक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था से पुनः 'हिन्दु रेट ऑफ ग्रोथ' पर पहुंच गया है।

अल्पकालिक है वर्तमान धीमापन

लेकिन 2013–14 के बाद ग्रोथ फिर से बढ़ने लगी, और वर्ष 2016–17 में नोटबंदी के बावजूद भी यह 7.2 प्रतिषत तक पहुंच गई। लेकिन पिछली तिमाही में ग्रोथ के घटने पर फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत फिर से मंदी में प्रवेष कर रहा है। इसके पीछे 'जीएसटी' और नोटबंदी को भी कारण बताया जा रहा है। लेकिन उधर मोर्गेन स्टेनली ने कहा है कि अगले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 2 खरब डालर से बढ़ती हुई 6 खरब डालर (तीन गुणा) हो जाएगी। यानि कहा जा सकता है कि यह धीमापन स्थायी रहने वाला नहीं है।

असमान वितरण और बेरोजगारी हैं मुख्य समस्याएं

हालांकि यह सही है कि 80–90 के दषक से प्रारंभ नई आर्थिक नीति अपनाए जाने के बाद जीडीपी ग्रोथ खासी तेज हो गई। हिसाब लगाया जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1990–91 में 11,535 रूपए ही थी, जो 2016–17 तक बढ़कर 1,15,428 रूपए हो चुकी है। यदि उसमें से कीमत वृद्धि (6.6 गुणा) घटा भी दी जाए तो ध्यान में आता है कि प्रतिव्यक्ति आय 3.4 गुणा बढ़ चुकी है। लेकिन क्या इस अनुपात में लोगों का कल्याण बढ़ा? क्या इस अनुपात में आम आदमी की आय बढ़ी? पता चलता है कि कदापि नहीं। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थषास्त्री थॉमस पिकेटी ने अपने एक लेख के माध्यम से बताया है कि वर्ष 1980 से 2014 के 34 वर्षों के बीच जीडीपी में जो भी वृद्धि हुई है उसका 66 प्रतिषत ऊपर के 10 प्रतिषत लोगों ने हस्तगत कर लिया और ऊपर के एक प्रतिषत लोगों के पास गोथ का 29 प्रतिषत चला गया। आंकड़े बताते है कि इस बीच स्वरोजगार में खासी कमी आई और उनके स्थान पर दिहाड़ीदाड़ मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 1990–91 में कुल उत्पादन का 78 प्रतिषत हिस्सा मजदूरी और वेतन में जाता था, जो वर्ष 2014–15 तक घटता हुआ मात्र 41 प्रतिषत रह गया। इसी बीच हम देखते हैं कि उत्पादन में लाभ का हिस्सा 19 प्रतिषत से बढ़ता हुआ 57 प्रतिषत पहुंच गया। यानि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो, जो ग्रोथ के इस युग में आम आदमी आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ गया।

मोर्गेन स्टेनली ने कहा है कि अगले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 2 खरब डालर से बढ़ती हुई 6 खरब डालर (तीन गुणा) हो जाएगी। यानि कहा जा सकता है कि यह धीमापन स्थायी रहने वाला नहीं है।

जब भी रोजगार की बात आती है तो हल्की सी चिंता जताते हुए अर्थषास्त्री कहते हैं कि यह रोजगारविहीन विकास है। हम देखते हैं कि एक तरफ जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार में कोई वृद्धि दिखाई नहीं देती। सॉफ्टवेयर, बीपीओ इत्यादि क्षेत्रों (जहां जनसंख्या का बहुत थोड़ा हिस्सा लगा हुआ है) में ही थोड़ा–बहुत रोजगार निर्माण हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में परंपरागत रोजगार में लगे हुए लोग अपनी जीविका खो चुके हैं। सभी अर्थषास्त्री कहते हैं कि कृषि में लोगों को बाहर कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिलाने की जरूरत है। लेकिन जहां गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहा हो तो ऐसे में कृषि क्षेत्र से लोगों को बाहर कैसे किया जा सकता है। ऐसे में किसान की बदतर होती स्थिति उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है।

असमानताएं भी हैं मंदी का कारण

बढ़ती असमानाओं के चलते यही नहीं कि आम आदमी का जीवन स्तर नहीं सुधर रहा, इसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी अब बाधित होने लगी है। कुछ समय पहले सामाजिक, आर्थिक जनसांख्यिकी की आंकड़े सरकार द्वारा प्रकाषित किए गए। उनसे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिषत परिवारों में अधिकतम आमदनी वाले सदस्य की आमदनी 10,000 रूपए मासिक से कम है और 75 प्रतिषत परिवारों में तो यह 5,000 रूपए मासिक से भी कम है। सर्वविदित है कि बिना आम आदमी की आमदनी बढ़ाए अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ सकती। अभी तक मध्यम वर्ग की मांग के सहारे उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा था। लेकिन मांग को और बढ़ाने के लिए जरूरी है कि निम्न–मध्यम वर्ग और उसके निचले तपकों की आमदनी भी बढ़े। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था में मांग स्थिर हो गई है, जिसके चलते जीडीपी ग्रोथ भी अब रूकने लगी है। मांग को बढ़ाने के लिए न केवल निम्न वर्ग की आय को बढ़ाना होगा, बल्कि ब्याज दरों को भी घटाना होगा, ताकि हाऊसिंग, औद्योगिक निवेष और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेष से जुड़ी मांग को भी बढ़ाया जा सके। निचले तपके के आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जीडीपी का यथासंभव समान वितरण किया जाए। ❑❑

स्वास्थ्यकारी A2 बनाम रोगकारी दूध A1

- **क्यों बढ़ रही है विदेशों में भारतीय नस्ल की गायों की मांग?**
- **क्या डायबिटीज, मधुमेह, बाल मनोविकार, गठिया आदि कई रोगों का विदेशी नस्लों A1 के दूध से संबंध है?**
- **हाल्स्टीन, जर्सी आदि गायों का A1 दूध क्या है?**
- **क्या भारतीय गोवंश का A2 दूध रोगों से बचाता व स्वस्थ रखता है?**
- **क्यों पूरे विश्व में A2 दूध की मांग बढ़ रही है?**

भारत में विदेषी नस्ल की गायों यथा जर्सी, हाल्सटीन, फ्रीजियन, रेड डेन आदि के A1 केसीनो प्रोटीनयुक्त दूध से आज कई प्रकार के रोगों की संभावनाओं में वृद्धि हो रही है। अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि कई देषों में गाय की विविध नस्लों के दूध की जाँच करने पर पाया गया कि सभी भारतीय नस्ल की गायें व अफ्रीकी नस्ल की गायें ए–2 या ए–2 केसीनों प्रोटीनयुक्त दूध देती हैं। यह देषी नस्ल की गायों का दूध व्यक्ति का हृदय रोग, मधुमेह, गठिया आदि कई रोगों से बचाता है व बच्चों में बुद्धिमत्ता विकसित करता है। वहीं दूसरी ओर यूरोप व अमेरिकी नस्ल की गायों यथा हॉल्स्टीन, जर्सी आदि ए–1 या ए–1 केसीनों प्रोटीनयुक्त दूध देती हैं, जिसका संबंध हृदय रोग, मधुमेह या डायबिटीज, गठिया, कैंसर आदि कई रोगों व बच्चों में स्वलनता (Autism) जैसे कई मनोविकारों से जोड़ा गया। इसके बाद यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि अनेक देषों में भारतीय नस्ल की गायों के A2 श्रेणी के दूध की मांग बढ़ी, डेयरी कंपनियों ने दूध के लेबल पर ही 'भारतीय नस्ल की गाय का A2 दूध' ऐसा लिखना भी प्रारंभ किया और अब उन देषों में बड़ी मात्रा में लोग A2 श्रेणी का दूध ही खरीदते हैं।

दुर्भाग्य से हमने भारत में अपने स्वास्थ्यवर्द्धक दूध देने वाली नस्लों के गौवंश को रोगकारी दूध देने वाली विदेशी संकर नस्लों में बदल दिया।
– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

दूध के 'केन', 'थैली' या 'बाटल' पर बहुसंख्य लोग A2 मार्क देखकर व उसका अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य चुकाकर भी खरीदते हैं। न्यूजीलैण्ड को अपनी गायों को भारतीय नस्ल में बदलने में 10 वर्ष का समय लगा। लेकिन उन्होंने अपने देष के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ यह किया। वर्ष 2000 में वहाँ A2 दूध के लिये एक A2 कार्पोरेषन नामक कंपनी तक बनी, जो अब आस्ट्रेलिया से आस्ट्रेलिया, चीन हांगकांग, अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि कई देषों में A2 दूध व उत्पादों का व्यवसाय करते है।

दुर्भाग्य से हमने भारत में अपने स्वास्थ्यवर्द्धक दूध देने वाली नस्लों के गौवंष को रोगकारी दूध देने वाली विदेषी संकर नस्लों में बदल दिया। आज भारत जो मधुमेह, हृदय रोग, गठिया, जैसे रोगों व बच्चों के स्वलीनता जैसे मनोविकारों की राजधानी बनता जा रहा है। हमारी बदलती जीवनशैली से जो व्यवहारगत व जीवनषैली जन्य कारणों के साथ–साथ इन रोगों व विकारों का संबंध विदेषी नस्लों की गायों के A1 श्रेणी के दूधे से भी जोड़ा जा रहा है।

अपने देष में शासकीय अनुदान एवं विविध कृषि व पषुपालन विष्वविद्यालयों के सहयोग से सभी डेयरियों व गौपालक परिवारों ने अपनी उत्तम A2 श्रेणी का दूध देने वाली गौ–नस्लों को कई रोगों से संबंध जोड़ने वाले A1 श्रेणी का दूध देने वाली संकट नस्लों के गौ–वंष में बदलने हेतु अब तक सभी प्रयास किये थे। अब अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैण्ड व ब्राजील आदि देषों में हुये अनुसंधानों के बाद धीरे–धीरे सरकारों व हमारे देष के भी विष्वविद्यालयों की धारणा बदलने लगी हैं। लेकिन अब हमारे यहां गायों की हमारी कई अपनी शुद्ध नस्लें ही नहीं बची है। ऐसे में ब्राजील जेसे देष जिन्होंने विगत 50 वर्षों में भारत से हमारी गायों की जिन नस्लों को ले जाकर उनका संरक्षण व संवर्द्धन किया है, हमें भी अब उन नस्लों के साण्डों या उनके वीर्य का आयात करना पड़ रहा है। लेकिन अब भी हमें युद्ध स्तर पर अपने गोवंष को यथासंभव बचाना है एवं उसका द्रुतगति से भारतीय नस्लों में जितना भी संभव हो बदलना चाहिये।

कई बीमारियों के अनेक कारण होते हैं। उनमें कुछ बीमारियों का संबंध A1 दूध से भी माना जा रहा है। उनमें 15–16 ऐसे रोग हैं, जिनका संबंध अन्य बातों के साथ–साथ A1 दूध से भी इनकी संभावना बन जाती है। अर्थात इन रोगों के प्रकट होने में A1 दूध भी एक कारक के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसा नहीं है कि A1 दूध से ये रोग हो ही जाते है, वरन अन्य कारकों के साथ मिलकर A1 दूध भी इन रोगों की उत्पत्ति में एक सषक्त कारक सिद्ध हो सकता है।

निम्न 16 रोगों के अन्य कारकों के साथ–साथ A1 दूध भी एक अहम् कारक बने, इसकी संभावना देखी जाने लगी है। वैसे इन रोगों व A1 दूध में अभी निष्चयात्मक संबंध स्थापित करने में समय लग सकता है। कई वैज्ञानिक अभी इससे सहमत नहीं है, वे और अधिक अनुसंधान की आवष्यकता मानते हैं। लेकिन, प्रथम दृष्ट्या अनेक वैज्ञानिक इन रोगों के पैदा होने में एक कारक A1 दूध मानते है।

- Arteriosclerosis | हृदयावरोध
- Schizophrenia | मनोविकार
- Autoimmune Disease | रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी
- Metabolic Disorder | चयापचय क्रिया संबंधी विकार
- Multiple Sclerosis | बहुविध ऊत्तकों में काठिन्य
- Parkinson's disease | पार्किंसन रोग में हाथों में कम्पनी
- Diabetes | मधुमेह
- Ulcerative colitis | आँतों में सूजन
- Heart Diseases | हृदय रोग
- Obesity | मोटापा
- Breast Cancer | स्तन कैंसर
- Digestive Disorder | पाचन क्रिया में विकार
- Hormonal Imbalance | हार्मोनल असंतुलन
- Liver Diseases | यकृत विकार
- Lactose intolerance | दुग्ध उत्पादों को न पचा पाना
- Alzheimer's Disease | भूलने की बीमारी

लेकिन इन 16 में से भी निम्न 4 रोगों की संभावना बहुत अधिक आंकी जा रही है।

1. इस्चीमिक हार्ट ड़िजीज (रक्तवाहिका नाड़ियों का अवरुद्ध होना व हृदयाघात)।
2. मधुमेह–मिलाईटिस या डायबिटिज टाईप–1 (पैंक्रिया का खराब होना जिसमें इन्सूलीन बनना बंद हो जाता है।)
3. आटिज्म (मानसिक रूप से बच्चों में स्वालीनता का विकार।)
4. षिजोफ्रेनिया (स्नायु कोषों का नष्ट होना तथा अन्य मानसिक रोग)।

अब भारत में भी A2 दूध के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। कुछ शहरों में A2 दूध का विपणन भी प्रारंभ हुआ है। इच्छुक परिवारों को A2 दुग्ध सहजता मंच द्वारा अतिथि गौषाला या जिसे गौ–छात्रावास भी कहा जाता है। यहाँ 20–25 गायें रख सकते हैं। वहाँ निष्चित लागत या आधे–आधे दूध के बँटवारे से अनुबंध पर प्रत्येक इच्छुक परिवार 1–2 गाय क्रय कर प्रायोजित कर उसका दुग्ध प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गौशालायें भी प्रामाणिक A2 दूध का विपणन प्रारंभ कर सकती है। वैसे इस पर एक राष्ट्रीय अभियान ही आवष्यक है, जिसमें देष के गौवंष को पुनः शुद्ध स्थानीय नस्लों में रूपांतरण किया जाये। ❑❑

दुनिया में फैलता चीन का आर्थिक साम्राज्यवाद

चीन ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का जो हश्र किया है, वो दूसरे देषों के लिए सबक हो सकता है। छोटे–छोटे देषों में चीन उन देषों की अर्थव्यवस्था को निवेष के नाम पर गुलाम बनाने की कोषिष कर रहा है। पहले ये देष निवेष की चकाचौंध में आ जाते हैं, लेकिन जब वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। चीन ने श्रीलंका को भी इसी प्रकार से दिवालियेपन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। करीब चार साल पहले कोलंबो से 250 किमी. दूर हब्बनटोटा में 'मताला राजपक्षे अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे' (MRIA) का चीनी मदद से निर्माण किया गया। जिसकी लागत 1.90 मिलियन डालर थी। यह हवाई अड्डा आज घाटे में चल रहा है। श्रीलंका, चीन के एक्जिम बैंक से लिया गया ऊंची ब्याज दरों का ऋण वापिस नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका ने अब यह हवाई अड्डा भारत को सौंपने का फैसला किया है ताकि वह चीन का कर्ज चुका सके।

इसी तरह हब्बरटोटा में ही चीन की कंपनियों द्वारा बनाई गई बंदरगाह को भी आर्थिक रूप से नुकसानदेह पाकर श्रीलंका ने चीन को 99 साल के पट्टे पर सौंप दिया है। भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस पट्टेनामें में यह शर्त जोड़ दी गई है कि चीन द्वारा इस बंदरगाह का उपयोग सैन्य दृष्टि से नहीं किया जायेगा। श्रीलंका को दिये गये कर्ज पर चीन 6.3 प्रतिषत ब्याज वसूलता है। जबकि विष्व बैंक व एषियाई विकास बैंक सिर्फ 0.25 से 3 प्रतिषत ब्याज दर पर ऋण देते है। भारत भी अपने पड़ोसी देषों को ऋण देता है तो उसकी ब्याज दर सिर्फ एक प्रतिषत होती है तथा कभी–कभी तो इससे भी बहुत कम। श्रीलंका धीमी विकास दर के कारण ऋण के पुर्नभुगतान में असमर्थ है। जिसके कारण वह ऋण को चीनी हिस्सेदारी में परिवर्तित कर रहा है।

चीन की यही रणनीति दूसरे छोटे देषों की अर्थव्यवस्था को भी निवेष के नाम पर अस्थिर करने की है। एषिया और अफ्रीका के दर्जन भर देषों में ओबोर परियोजना (OBOR)

चीन की रणनीति दूसरे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था को भी निवेश के नाम पर अस्थिर करने की है।
– दुलीचन्द रमन

के नाम पर करीब एक ट्रिलियन डालर निवेष के माध्यम से बंदरगाह, सड़कें, रेल लाईने तथा दूसरे निर्माण कार्य कर रहा है। ये सब निर्माण कार्य चीनी कंपनियों द्वारा किये जा रहे है। जो ज्यादातर चीनी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां है। इससे सीमेंट, स्टील की खपत बढ़ रही है। रोजगार बढ़ रहे है। जिसके कारण चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था को हवा मिल रही है।

ओबोर परियोजना में कुल छः कॉरिडोर बनाये जाने की योजना है। भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देष इस परियोजना में हिस्सेदारी की इच्छा रखते है। भारत को 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (CPEC) को लेकर विरोध है जो कि पाकिस्तान अधिकृत कष्मीर से होकर गुजरता है। खुद पाकिस्तान के कबाईली इलाकों में इस परियोजना का विरोध हो रहा है। 2014 से जुलाई 2017 तक इस परियोजना में लगे 64 चीनी अधिकारी/कर्मचारी मारे जा चुके है। पाकिस्तान के बुद्विजीवी वर्ग में भी चीन के प्रति शंका बढ़ती जा रही है। जानकारों का मानना है कि इस योजना में चीन का पाकिस्तान में 80 प्रतिषत, म्यांमार में 50 प्रतिषत और मध्य एषिया में 30 प्रतिषत निवेष डूब जायेगा। लेकिन महाषक्ति बनने की ललक में चीन यह जुआ खेलने को तैयार बैठा है।

ओबोर परियोजना के अंतगर्त दिये जाने वाले कर्ज़ की भी ब्याज दर ऊंची होती है। ऋण के पुर्नभुगतान में संबंधित देष की असमर्थता की स्थिति में परियोजना में स्थाई हिस्सेदारी खरीदकर चीन उस देष की व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप शुरू कर देता है।

पिछले दिनों चीन ने बंगलादेष को 24 विलियन डालर वित्तीय मदद दी थी। चीन अब बंगलादेष पर इस मदद को वाणिज्यिक ऋण में बदलने का दबाव डाल रहा है। जिससे बंगलादेष को उस पर ब्याज की उंची दर चुकानी होगी। बंगलादेष ऋण की प्रकृति में परिवर्तन के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो वह भी श्रीलंका की तरह चीन के ऋण जाल में फसकर अपनी स्वायत्तता गवां बैठेगा। चीनी राष्ट्रपति की ढाका यात्रा के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चीन द्वारा कुछ परियोजनाओं से निवेष पर सहमति बनी थी। चीनी अधिकारी चाहते है कि बंगलादेष सरकार उन परियोजनाओं में भी सांझीदार के तौर पर निवेष करे। यह बंगलादेष जैसे छोटी अर्थव्यवस्था

चीन की जीडीपी भारत से पांच गुणा बड़ी है। इसलिए भारत की भी अपनी सीमायें है। क्योंकि भारत की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की अभी भी बहुत संभावनायें है।

के देष के लिए संभव नहीं है। भारत ने चीनी चाल को समझते हुए बंगलादेष को 7.5 बिलियन डालर की वित्तीय मदद मात्र एक प्रतिषत ब्याज दर पर दी है।

ये सच है कि चीन की जीडीपी भारत से पांच गुणा बड़ी है। इसलिए भारत की भी अपनी सीमायें है। क्योंकि भारत की घरेलू आवष्यकताओं की पूर्ति की अभी भी बहुत संभावनायें है। फिर भी हम अपने पड़ोसी देषों की स्थिति से नज़र फेरकर नहीं बैठ सकते।

नेपाल के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन है। लेकिन चीन ने इस शांत देष को वामपंथी विचारधारा से प्रेरित गृहयुद्ध में धकेल दिया। बाद में राजषाही के खात्मे के बाद बनी वामपंथी सरकारों का चीन के प्रति मोह रहा। लेकिन अब जैसे–जैसे नेपाली सरकार को चीन की मानसिकता के बारे में ज्ञान हुआ है तभी से वह चीन और भारत के बीच संबंधों में संतुलन साधने की कोषिष कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री की अगस्त 2017 की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत ने भूकम्प से प्रभावित हुए लोगों के लिए पचास हजार घर बनाने में मदद की पेषकष नेपाल की थी। चीन ने इस मदद पर तंज कसते हुए कहा कि भारत पहले अपना घर सुधारे। भारत अगर नेपाल को मदद देता भी है तो इससे नेपाल के लोगों की क्रय–षक्ति बढ़ेगी जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नेपाल में कार्य कर रही चीनी कंपनियों को ही होगा।

अभी तक चीन का व्यापारिक युद्ध के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ विजय अभियान जारी है। चीन अब पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेष सहित विष्व के 100 देषों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। चाईना विकास बैंक (CDB) और आयात–निर्यात बैंक (Exim Bank) अफ्रीका में इतना निवेष कर रहे है, जितना अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष और विष्व बैंक मिलकर भी नहीं कर रहे। हाल ही में इक्वाडोर और वेनेजुएला की गिरती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर इन देषों को चीन ने ऊंची ब्याज दर पर आर्थिक सहायता की है। चीन विष्व का सबसे बड़ा सूदखोर बन चुका है। मंगोलिया की अर्थव्यवस्था पर चीन का कब्जा किस प्रकार हो चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगोलिया का नब्बे प्रतिषत निर्यात चीन को होता है। जिससे वह कभी भी मंगोलिया के साथ सीमा–विवाद अपने पक्ष में हल कर सकता है।

चीन समुद्री सीमा में भी अपनी सैन्य ताकत का अखाड़ा बनाना चाहता

है। इसी प्रयास में उसने अफ्रीकी देष जिबूती में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। जहां चीन के दस हजार सैनिक रहेंगे। यह मुख्य चीनी भूमि से दूर पहला नौसैनिक अड्डा है। चीन इसी प्रकार की नौसैनिक गतिविधियां चलाने की मंषा से पाकिस्तान में 'ग्वादर' बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। चीन को पता है कि हिन्द महासागर और अरब सागर क्षेत्र में भारतीय सेना की ताकत का दबदबा है। पिछले दिनों भारतीय नौसेना ने जापान व अमेरिका के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में 'मालावार–2017' अभ्यास भी किया था। समुद्री सीमा में चीन को जापान, ताईवान, फिलिपिन्स, इंडोनेषिया द्वारा चुनौतियां पेष की जा रही है। अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में 'स्वतंत्र नौवहन' के बहाने अपनी गतिविधियां चलाता रहता है। जिसका चीन की नौसेना के साथ टकराव होता ही रहता है।

आजकल पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर विष्व बिरादरी में बदनाम हो चुका है। वह अमेरिका से करोड़ों डालर डकारकर उसे ही धोखा देता रहा। अमेरिका द्वारा खरी–खोटी सुनने के बाद पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। हिन्द महासागर में भी उनकी नौसैनिक जुगलबंदी दिखाई दे रही है। चीन के युद्वपोत अब कराची और ग्वादर में रह सकेगे। इसके साथ–साथ चीन पाकिस्तान को युद्वपोत तथा पनडुबडी भी मुहैया करायेगा। ताकि भारत की हिन्द महासागर में बढ़ती सैन्य ताकत को संतुलित किया जा सके।

अभी तक अमेरिका व जापान विष्व के देषों को विकास हेतु ऋण देते थे। लेकिन अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान, इराक, सिरिया में युद्धों के कारण तथा जापान की धीमी अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया में कई देषों को चीन की तरफ देखना पड़ता है। चीन द्वारा उन देषों को यह मदद उन देषों के बाजार और राजनीतिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने के मकसद से की जाती है। इस मदद से उस देष का भला भले ही न हो लेकिन चीन का लाभ जरूर होता है क्योंकि ओबोर परियोजना के माध्यम से उसके सस्ते उत्पादों का अष्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बे–खौफ दुनिया के बाजारों में दौड़ने को लालायित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की विरोधाभाषी नीतियां भी चीन के बढ़ते हौंसले का कारण बनी हुई है। अमेरिका अफगानिस्तान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका चाहता है क्योंकि वहां अमेरिका की टांग फंसी हुई है लेकिन अमेरिका डोकलाम के मुद्दे पर अपनी जुबान नहीं खोलता। भारत को वर्तमान परिस्थितियों में बदलते वैष्विक शक्ति संतुलन में सोच–समझकर कदम उठाना होगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कैसे करें उपयोग

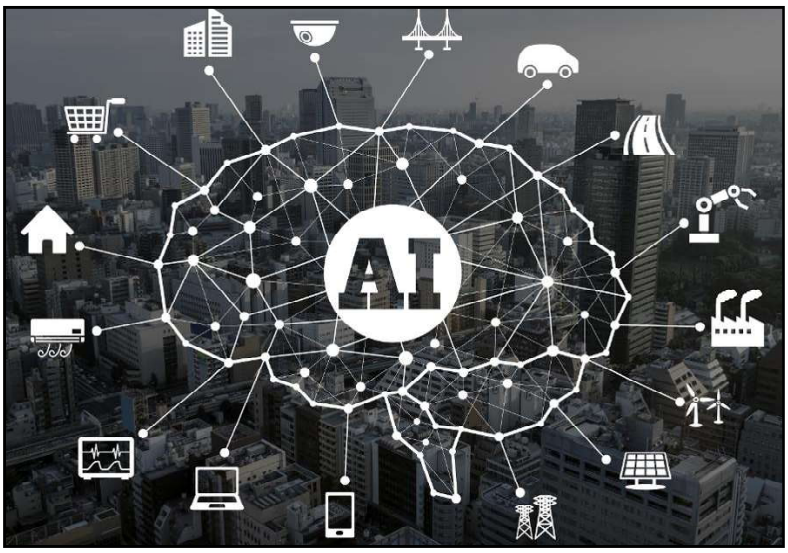

वाणिज्य मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर टास्क फोर्स गठित किया है। टास्क फोर्स सरकार को सलाह देगी कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेश कैसे किया जाए। कम्प्यूटर द्वारा किए गए बौद्धिक कार्य को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कहा जाता है। जैसे वर्तमान में आपको कोर्ट में कोई वाद दायर करना हो तो वकील साहब का जूनियर उस तरह के पूर्व में हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का अध्ययन करता है। इसके बाद वकील साहब विचार करते है कि कौन से निर्णय हमारे लिए लाभकारी होंगे। जो निर्णय हमारे वाद के विपरीत दिखते है उनकी काट में कौन से दूसरे निर्णय कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जा सकते है। तब तय होता है कि वाद दायर करने लायक है या नहीं। तमाम समतुल्य निर्णयों का अध्ययन करने का कार्य अब कम्प्यूटर द्वारा किया जा रहा है। आप कम्प्यूटर को बताऐंगे कि आपकी समस्या क्या है। कम्प्यूटर कोर्ट के तमाम निर्णयों को खंगालेगा। इसके बाद आपको 2–4 निर्णय देगा जो कि आपके पक्ष में होंगे; और 2–4 निर्णय देगा जो कि आपके विपक्ष में होंगे। विपक्ष के निर्णयों की काट को दूसरे निर्णय बताएगा। इस रिसर्च के बाद आपके वकील के लिए वाद दायर करने में सहूलियत होगी।

भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर टास्क फोर्स बनाए जाने का स्वागत है। जरूरत है कि इस उभरते क्षेत्र के प्रति हम सकारात्मक रूख अपनाए। विशेषकर उन सेवाओं पर ध्यान दें, जो कम्प्यूटर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

कम्प्यूटर द्वारा दिए गए इस बौद्धिक कार्य के रोजगार पर दो परस्पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि वकील साहब के जूनियर का रोजगार समाप्त हो जाएगा। पूर्व में वकील साहब जूनियर से उपरोक्त रिसर्च कराते थे जो अब कम्प्यूटर कर देगा। लेकिन कम्प्यूटर की मदद से वाद सही ढंग से बन सकेंगे। अक्सर देखा जाता है कि वकील को वाद के विपरीत निर्णयों की जानकारी नहीं होती है। कोर्ट में प्रस्तुत होने पर वाद खारिज कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग से वादों में सफलता के प्रतिशत में सुधार होगा, लोगों का वाद दायर करने का साहस बढ़ेगा, वादों की संख्या में वृद्धि होगी और वकीलों के कुल रोजगार में भारी वृद्धि हो सकती है।

रोजगार पर इसी तरह का सुप्रभाव बुनाई करने की मशीनों का पड़ा था। आज से 500 वर्ष पूर्व एक आविष्कारक इंग्लैंड की महारानी एलीजाबेथ प्रथम के पास गए और स्वेटर की बुनाई करने की मशीन के आविष्कार का पेटेंट जारी करने का निवेदन किया। महारानी ने पेटेंट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ''मेरी उन गरीब महिलाओं और असंरक्षित कुंआरियों के प्रति अपार सहानुभूति है जो कि बुनाई करके अपनी दैनिक रोटी अर्जित करती है। मैं ऐसे अविष्कार को नहीं बढ़ा सकती हूं जो उन्हें उनकी जीविका से वंचित करके

भूखमरी के द्वार पर लाकर खड़ा कर दे।'' महारानी द्वारा पेटेंट न दिए जाने के बावजूद बुनाई मशीनों का उपयोग बढ़ा। तमाम कुंआरियां बेरोजगार हो गई। परंतु साथ–2 बुनी हुई स्वेटर के दाम में भारी गिरावट आई। लोगों ने ज्यादा मात्रा में स्वेटर खरीदना चालू किया। बुनाई की मशीनें बनाने, मशीनों की देखरेख करने, ज्यादा मात्रा में बने माल की पैकिंग एवं वितरण करने, मशीन से नई डिजाइन की स्वेटर बनाने इत्यादि में तमाम नए रोजगार बने। अंत में बुनाई मशीन का समाज एवं अर्थव्यवस्था पर सुप्रभाव पड़ा। जो कुआरियां स्वेटर बुनकर अपनी दैनिक रोटी अर्जित करती थी वे अब स्कूल जाने लगी। पढ़कर वे मशीन पर डिजाइन करने का रोजगार प्राप्त करने लगी। आम आदमी को स्वेटर की उपलब्धता भी बढ़ी। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रभाव कुछ ऐसा ही होगा। एक तरफ वकील के जूनियर का रोजगार समाप्त होगा तो दूसरी तरफ कोर्ट में दायर किए जा रहे वादो की संख्या में वृद्धि होगी। अधिक संख्या में लोगों को न्याय मिलेगा और समाज खुशहाल होगा।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का सामना करने के लिए हमें अपने युवाओं को उन रोजगारों को हासिल करने के लिए सक्षम बनाना होगा जो कि कम्प्यूटर के उपयोग के बाद भी बनते रहेंगे। जैसे आनलाइन ट्यूटोरियल को कतिपय कम्प्यूटर से छात्र हासिल कर सकता है। परंतु बच्चों को नर्सरी स्कूल में शिक्षा कम्प्यूटर से कम ही दी जा सकेगी। छोटे बच्चे नर्सरी में जाने पर रोते है। उन्हें मां का प्यार चाहिए जो कम्प्यूटर कम ही दे सकता है। इसलिए हमें दोनों स्तर पर कार्य करना होगा। एक तरफ अपने युवाओं को आनलाइन ट्यूटोरियल के साफ्टवेयर बनाने की ट्रेनिंग देनी होगी जिससे वे उत्तम क्वालिटी का साफ्टवेयर बना सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। दूसरी तरफ नर्सरी शिक्षा की ट्रेनिंग देनी होगी चूँकि अधिकाधिक संख्या में अभिभावकों द्वारा बच्चें को नर्सरी स्कूल में भेजा जाएगा।

इसी तरह स्वास्थ के क्षेत्र में आनलाइन सलाह उपलब्ध हो सकती है। ऐसा साफ्टवेयर संभवतः बनाया जा सकता है जिसमें आप अपनी बीमारी का पूरा विवरण दर्ज करें जैसे बुखार, बीपी, शुगर, खांसी की अवधि, पसीना आना, इत्यादि। इसके बाद साफ्टवेयर द्वारा आपसे कुछ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते है। इनका जवाब देने के बाद कम्प्यूटर आपको पर्चा लिखकर दे सकता है। ऐसा साफ्टवेयर बनने से लोगों को मेडिकल सलाह सस्ते में उपलब्ध हो सकती है। उन्हें स्वास्थ लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस क्षेत्र में भी दो तरह से अपने युवाओं को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उन्हें मेडिकल सलाह देने के साफ्टवेयर लिखने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मेरे एक मित्र के युवा बेटे ने गोल्फ के खिलाड़ियों को सलाह देने का साफ्टवेयर बनाया है। खिलाड़ी को अपने स्ट्रोक की विडियो साफ्टवेयर में लोड करनी होती है। साफ्टवेयर विश्लेषण करके बताता है कि स्ट्रोक को कैसे सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार बीमारियों के विश्लेषण के साफ्टवेयर लिखे जा सकते हैं। बीमारियों का उपचार अलग–2 क्षेत्रों में अलग पद्धतियों से किया जाता है। अतः तमाम बीमारियों, तमाम उपचार पद्धतियों एवं तमाम भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग–2 साफ्टवेयर लिखे जा सकते है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ के क्षेत्र में ही तमाम ऐसे कार्य है जो संभवतः कम्प्यूटर द्वारा कभी न किए जा सके। जैसे घुटना बदलने की सर्जरी करना, फिजियोथेरापी कराना, पंचकर्म का उपचार करना इत्यादि। स्वास्थ उपचार के आनलाइन उपलब्ध हो जाने से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। इस उभरती मांग को रोजगार में बदलने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देना जरूरी है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का सामना करने के लिए हमें अपने युवाओं को उन रोजगारों को हासिल करने के लिए सक्षम बनाना होगा जो कि कम्प्यूटर के उपयोग के बाद भी बनते रहेंगे।

कुछ क्षेत्र है जिनमें कम्प्यूटर द्वारा सुविधाएं शायद कभी भी उपलब्ध न कराई जा सके। वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने इस विषय पर कुछ विशेषज्ञों से बातचीत की, जिन्होंने सुझाया कि उन स्किल की भविष्य में ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो ''सृजनात्मक है, सहभागिता आधारित है, जो विभिन्न वातावरणों में कार्य कर सकते है, जो विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकते है, और जिनमें सामाजिक एवं भावनात्मक क्षमता है।'' ये क्षमताएं आर्ट्स से संबंधित है जैसे भाषा, संस्कृति, पेंटिग, कला, साहित्य आदि से। इन क्षेत्रों में कम्प्यूटर द्वारा प्रवेश कठिन है जैसे तुलसी की रामायण अथवा बाइबल को कम्प्यूटर शायद ही लिख सके। अतः हमें अपनी युवा पीढ़ी को आर्ट्स के विषयों के महत्व को समझाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर टास्क फोर्स बनाए जाने का स्वागत है। जरूरत है कि इस उभरते क्षेत्र के प्रति हम सकारात्मक रूख अपनाए। विशेषकर उन सेवाओं पर ध्यान दें, जो कम्प्यूटर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। आर्ट्स और कम्प्यूटर के जोड़ से नए क्षेत्रों में हमारे युवा रोजगार हासिल कर सकेंगे। इस दिशा में टास्क फोर्स को सोचना चाहिए। ❑❑

उद्योगों के विकास के लिए खेती की बलि?

चलिए आज मैं आपको विक्रम और बेताल की कहानी सुनाता हूं। यह पूछने से पहले कि इसका कृषि संकट से क्या लेना–देना है, मेरा सुझाव है कि आप कहानी सुन लीजिए। विक्रम, बेताल को अपनी पीठ पर लाद ले जा रहा था और बेताल ने हमेषा की तरह उनसे एक सवाल पूछ लिया, 'एक पिता के तीन बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा प्रबुद्ध और मेधावी बुद्धि वाला था, बीच वाला सामान्य बुद्धि वाला आम आदमी था, तीसरे में कुछ विकलांगता थी। पिता के पास एक रोटी थी जिसे उसे अपने तीनों बेटों में बांटनी थी। अब ये बताओ कि वो उस रोटी को किस अनुपात में अपने बेटों के बीच बांटेगा?'

ये कहानी कुछ दिन पहले देष के विख्यात पुराणषास्त्री देवदत्त पटनायक द्वारा प्रसिद्ध पत्रकार शोमा चौधरी के साथ गुड़गाँव में बातचीत करते हुए सुनाई गई थी। उन्होंने दर्षकों से कहा कि घर पहुंचने के बाद सोच समझकर इस प्रष्न का जवाब दें परंतु साक्षात्कार शोमा चौधरी ने झट से उत्तर देते हुए कहा, 'स्पष्ट है कि वो रोटी के तीन बराबर टुकड़े करके तीनों को देंगे।' इस पर पटनायक ने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि विकलांग पुत्र को एक तिहाई रोटी मिलेगी तो उसे आवष्यकतानुसार पोषण नहीं मिल पाएगा, इसी प्रकार यदि सबसे बड़े पुत्र को एक तिहाई रोटी मिलेगी तो उसकी बुद्धि के पोषण के लिए भी वह कम पड़ेगी, इसलिए पिता को बहुत सोच समझकर निर्णय लेना था।'

देवदत्त पटनायक ने समझाया कि हम जो सैद्धांतिक मान्यताएं बनाते हैं उनमें और वास्तविकता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। किसी ध्येय अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ बलिदान देने की भी आवष्यकता होती है। फिर उन्होंने निर्णायक तौर पर कहा, 'अगर आपका उद्देष्य उद्योग को बढ़ावा देना है तो आपको कृषि का बलिदान देना होगा।' आगे वो बोले कि आप ये नहीं कह सकते कि आप उद्योग को बढ़ावा देना चाहते है पर कृषि को भी व्यवहार्य बनाये रखना चाहते हैं। इस प्रकार काम नहीं हो सकता है। दोनों में से एक क्षेत्र को हानि झेलनी होगी।

भारत को देखें तो वास्तव में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों में 70 प्रतिशत मामलें कपास किसानों के होते हैं। ये किसान एक सोची समझी नीति के शिकार हैं जिन्हें उनको उचित आय प्राप्त करने से रोका जाता है ताकि वस्त्र उद्योग फल फूल सके।

– देविंदर शर्मा

वो बिलकुल ठीक कह रहे हैं। जब से 1991 में आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया था तभी से अनुवर्ती सरकारें यही करती आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योग को बढ़ाने के लिए कृषि का बलिदान दिया गया है। वस्तुतः मैं कई बार कह चुका हूं कि आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाये रखने के लिए कृषि की बलि दी जा रही है और जैसा आप जानते हैं आर्थिक सुधार उद्योग से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए एक प्रकार से देवदत्त पटनायक ने उसी बात की पुष्टि की है, जो मैं लम्बे समय से कहता आया हूं। कृषि की भूमिका उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध करवाने, रियल एस्टेट और अवस्थापना सहित उद्योग के लिए भूमि उपलब्ध करवाने और उद्योग के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करवाने तक सिमट गई है।

नीति निर्धारकों के लिए किसानों की केवल दो भूमिकाएं हैं – या तो वो वोट बैंक समझे जाते हैं या भूमि बैंक।

मैं नहीं जानता कि विक्रम ने बेताल को क्या जवाब दिया लेकिन यदि आप खाली समय में बैठकर विचार करें तो आप मानेंगे कि देवदत्त पटनायक ने बहुत पते की बात कही है। दो उदाहरण पेष करके मैं आपके सामने इस बात को सिद्ध करता हूं। 1990 के दषक के शुरुआत में जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार था, मुझे याद है कि मैंने कृषि लागत और मूल्य आयोग की खरीफ रिपोर्ट का अध्ययन किया था। फसल उगाने के प्रत्येक मौसम में कृषि लागत और मूल्य आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें फसलों के न्यूनतम लागत मूल्य की गणना की जाती है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि कई वर्षों से वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कपास किसानों को वैश्विक बाज़ार कीमतों से 20 प्रतिषत कम भुगतान किया जा रहा था। यही नीति अब भी जारी है।

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वस्त्र उद्योग को व्यवहार्य रखने के लिए कपास किसानों को 20 प्रतिषत कम भुगतान किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कपास की कीमत कम होने का कारण है अमेरिका द्वारा अपने कपास किसानों को दी जाने वाली वृहत सब्सिडी। 2005 में मैंने हांगकांग डब्ल्यूटीओ मिनिस्टीरियल के दौरान किए गए अपने विस्तृत अध्ययन के दौरान बताया था कि अमेरिकी सब्सिडी किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में गिरावट लाती है जिसके परिणामस्वरूप भारत और पष्चिमी अफ्रीका के किसान अयोग्य उत्पादक प्रतीत होते हैं।

किसानों की औद्योगिक विकास की वेदी पर बलि दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष तय किया जानेवाला न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तव में खेती के उत्पादन मूल्य से कम होता है।

'योर सब्सीडीज़ किल आवर फार्मर्स' शीर्षक से लिखे गए एक पत्र, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाषित किया गया था, उसमें चार पष्चिमी अफ्रीकी देषों के प्रमुखों ने बिलकुल स्पष्टता से दर्षाया था कि किस प्रकार अमेरिका द्वारा दी जा रही सब्सिडी अफ्रीका के कपास किसानों का जीना दूभर कर रही है। हम कितनी सब्सिडी की बात कर रहे हैं? 2005 में अमेरिका ने केवल 20,000 किसानों को 3.9 बिलियन डॉलर मूल्य की फसल की पैदावार के लिए 4.7 बिलियन डॉलर की सब्सिडी प्रदान की थी।

ये बड़ी भारी कपास सब्सिडी अमेरिकी वस्त्र उद्योग को व्यवहार्य रखने के लिए दी गई थी। इसके पीछे किसानों की सहायता करने का भाव नहीं था बल्कि ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रोत्साहन था। कपास सब्सिडी वैश्विक कीमतों में गिरावट लाती हैं जिसके कारण भारत और अफ्रीका के किसान कपास के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सस्ते और बड़े स्तर पर सब्सिडी प्राप्त वस्त्र भारत, चीन और अन्य विकासषील देषों द्वारा आयात किए जाते हैं। भारत को देखें तो वास्तव में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों में 70 प्रतिषत मामले कपास किसानों के होते हैं। ये किसान एक सोची समझी नीति के षिकार हैं जिन्हें उनको उचित आय प्राप्त करने से रोका जाता है ताकि वस्त्र उद्योग फल फूल सके।

किसानों की औद्योगिक विकास की वेदी पर बलि दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष तय किया जानेवाला न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तव में खेती के उत्पादन मूल्य से कम होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग इस बात को मानता है परंतु उसकी भूमिका किसानों को भुगतान की कीमतों और उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य के बीच संतुलन बनाना है। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को खुष रखने के लिए किसानों को गुरबत में रखा जा रहा है। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि वर्ष दर वर्ष वास्तव में किसान उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं?

मैं और मेरे दल के सदस्य एक अध्ययन रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं जिसमें ये सामने आया है कि भारत के किसानों से हर वर्ष 12.60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है। हर वर्ष उद्योग और उपभोक्ताओं को खुष रखने के लिए उन्हें इस राषि से वंचित रखा जा रहा है। ये है वो आर्थिक बलिदान जो उद्योग को व्यवहार्य रखने की खातिर कृषि से लिया जा रहा है। ❑❑

लागत घटे, तो खेती बनें उत्तम

हालांकि यह कहना अन्याय होगा कि सरकार न तो फसली उत्पाद का न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य बढ़ायेगी और न ही न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य, पर अधिकतम फसल की खरीद सुनिश्चित करेगी, बेहतर हो कि किसान अपने उत्पादन की लागत घटाये; लेकिन सरकारी रवैये और कर्ज माफी से संतुष्ट हो जाने के रूप में किसान संगठनों द्वारा पेश नरमी का यथार्थ यहीं है। यथार्थ यह भी है कि न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य को लागत के डेढ़ गुना तक बढ़ाने को लेकर केन्द्र सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। हमारी सरकारों की रुचि न तो न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य के दायरे में शामिल फसलों की सरकारी खरीद की क्षमता बढ़ाने में है और न ही किसान को न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य से कम पर फसल बेचने के लिए विवश करने वाले खुले बाज़ार पर सख्ती बरतने में। इसके लिए सरकारों के अपने तर्क हैं। उत्पादक से उपभोक्ता के बीच सक्रिय दलालों के मुनाफे को नियंत्रित करने में भी सरकारों की कोई खास रुचि दिखाई नहीं दे रही। यह रुचि पैदा करना ज़रूरी है। इसके लिए जन दबाव बनाने के जो भी शांतिमय तरीके हों; आजमाने चाहिए। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और बाज़ार–दोनों ही कभी भी किसान के नियंत्रण में नहीं रहे। जब तक किसान अपनी फसल के भंडारण की स्वावलंबी क्षमता हासिल नहीं कर लेता; तब तक आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं होने वाली; लिहाजा, सरकार, कर्ज़ और बाज़ार के भरोसे खेती करना अब पूरी तरह जोखिम भरा सौदा है। अतः यह ज़रूरी है कि फसल उत्पादन लागत में घटोत्तरी के उपायों पर अमल शुरु हो। यह कैसे हो?

सरकार, कर्ज़ और बाज़ार के भरोसे खेती करना अब पूरी तरह जोखिम भरा सौदा है। अतः यह ज़रूरी है कि फसल उत्पादन लागत में घटोत्तरी के उपायों पर अमल शुरु हो।
– अरूण तिवारी

कृषि में लागत मूल्य के मुख्य 10 मद हैं : भूमि, मशीनी उपकरण, सिंचाई, बीज, खाद, कीट–खरपतवारनाशक, मड़ाई, भंडारण, समय और आवश्यक श्रम। कृषि ज़रूरत की इन सभी चीजों पर किसान का स्वयं का नियंत्रण हुए बगैर, न कृषि की लागत घटाई जा सकती है और न ही खेती को स्वाभिमानपूर्वक उदर–पोषण करने वाले कार्य की श्रेणी में लाया जा सकता है। जो भूमिहीन किसान, दूसरों के खेत किरायेदारी पर लेकर खेती करते हैं, उनकी भूमि किरायेदारी लागत घटाने के लिए जबरन किया गया कोई भी प्रयास, अंततः सामाजिक विद्वेष खड़ा करने वाला साबित होगा। जैसे–जैसे खेत मालिक की शर्त पर श्रम की उपलब्धता घटती जायेगी, यह लागत स्वतः कम होती जायेगी; यह भरोसा रखें।

दूसरा पहलू देखें तो सस्ते श्रम की उपलब्धता घटने से खेती में श्रम की लागत बढ़ी है। इसका एक पक्ष यह भी है कि बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, मड़ाई आदि के जो काम मानव श्रम से संभव थे, अब उन्हें आधुनिक मशीनी उपकरणों से करने की बाध्यता है। किंतु भारत के ज्यादातर किसानों के पास कृषि जरूरत के सभी उपकरण खरीदने की क्षमता नहीं है। इस तरह आधुनिक मशीनी उपकरण, बड़े किसान के लिए तो एक मुश्त लागत का मद हैं, लेकिन छोटे किसानों को हर फसल पर इनके सेवा ठेकेदारों को दाम चुकाना पड़ता है, जोकि काफी अधिक होता है। हमारे वैज्ञानिक व इंजीनियरों ने सस्ते, स्वावलंबी और लंबी

आयु वाले कृषि उपकरण ईजाद तो कई किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर के व्यापक उत्पादन को सरकारों ने प्रोत्साहन नहीं दिया। बायोवेद संस्थान, श्रृंगवेरपुर (इलाहाबाद) में एक बैल मात्र चलने वाला कोल्हूनुमा टयुबवैल बिना बिजली–डीजल तीन इंच पानी देता है। सरकार, बिजली में तो सब्सिडी देती है, लेकिन बिना बिजली चलने वाले उपकरणों को प्रोत्साहित करने में दिलचस्पी नहीं रखती। बिना मवेशी, बिजली, ईंधन चलने वाले 'मंगलसिंह टरबाइन' को ईजाद करने वाले किसान मंगलसिंह (ज़िला ललितपुर, उ.प्र.) को तो उल्टे हतोत्साहित किया गया। शेष जो कृषि उपकरण, उद्योगपतियों और व्यापारियों की शरण में पहुंचे, वे किसान तक, मंहगे होकर ही पहुंचे। लिहाजा, कृषि मशीनी उपकरण खरीद और उपयोग लागत घटाने का तात्कालिक उपाय यहीं है कि किसान मशीनी उपकरण खरीद तथा रखरखाव की सामिलात व्यवस्था करें। सामिलात व्यवस्था होगी, तो एक ही उपकरण 20–25 किसानों के काम आ सकेगा। उपकरण खराब होने पर ठीक करने के हुनर को भी किसान समूहों को खुद ही हासिल करना होगा। इससे लागत घटेगी; साझा बढ़ेगा। साझा बढ़ते ही लागत घटोत्तरी के कई मार्ग स्वतः खुल जायेंगे। उपज की खरीद–फरोख्त भी बाज़ार की जगह, पहले आपस में होने लगेगी। इससे लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। पारंपरिक खेती और बार्टर पद्धति का सद्गुण यहीं था।

खर–पतवारों की अधिकता ने भी श्रम लागत बढ़ाई है। जिस इलाके में जो खर–पतवार कभी नहीं होते थे, खेत अब उनसे पटे पड़े हैं। कारण, षडयंत्र है। ये खर–पतवार, कंपनियों द्वारा उर्वरकों तथा बीजों में मिलावट कर खेतों तक पहुंचाये जा रहे हैं; ताकि कंपनियों की खर–पतवार नाश करने वाले जहरीले रसायन बिकें। जो किसान, इन जहरीलों से रसायन से बचे रहना चाहते हैं, उन्हें मानव श्रम लगाकर खर–पतवार उखाड़ते हैं। स्पष्ट है कि बचत तभी हो सकती है कि जब बाज़ार से उर्वरक और बीज न खरीदने पड़ें। यदि ऐसा हो गया तो बीज और उर्वरक मद में लागत खर्च तो स्वतः घट जायेगा। उपाय साधारण हैं, लेकिन धीरज चाहिए।

शुरुआत देसी बीज संजोने से संभव है। मिश्रित बीज बोयें। मतलब यह कि गेहूं की बुआई करनी है, तो एक खेत में गेहूं के ही कम से कम दो तरह के देसी बीज मिश्रित करके छींट दें। उनसे जो फसल पैदा होगी, वह स्वतः उन्नत किस्म की होगी प्राप्त फसल को अगले वर्ष बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऐसे प्रयोग लगातार करें और जांचें। यदि देसी बीज उपलब्ध नहीं है, तो बाज़ार से ऐसा–वैसा बीज खरीदने की बजाय, 'ब्रीडर सीड' व 'फाउण्डेशन सीड' ही खरीदें; ताकि आप अपनी भावी ज़रूरत का बीज खुद तैयार कर सकें।

उर्वरक व कीटनाशकों से मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है जैविक खाद।

उर्वरक व कीटनाशकों से मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है जैविक खाद। कंपोस्ट खाद, केचुंआ खाद, मानव मल की खाद और हरी खाद के अलावा गोमूत्र, गुड़ आदि के मिश्रण से जैविक खाद बनाने जैसे कई प्रयोग इधर चर्चा में आये हैं; इन्हें अपनायें। मवेशियों की संख्या बढ़ायें। मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए चारे वाले पौधे व फसल तो लगायें ही, मवेशियों को उनके चारागाह लौटायें। जैसे ही किसान खेत से रासायनिक उर्वरक हटायेगा; जैविक खाद तीन लाभ साथ लायेगी। जैविक खाद, केचुओं आदि भू–जीवों को न्यौता देकर ऊपर बुला लेती है। लिहाजा, आप देखेंगे कि मिट्टी की उर्वरकता हर साल घटने की बजाय, बढ़ने लगेगी। जैविक खाद, मिट्टी के ढेलों को बांधकर रखती है। लिहाजा, कम सिंचाई में भी खेत में ज्यादा लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। बहुत संभव है कि एक बारिश होने पर सरसों, चना, मटर जैसी फसलें बिना सींचे ही होने लगें। इससे सिंचाई खर्च घटेगा। कीटनाशक को खेत से बाहर करने के तीन साल के भीतर अपने बच्चों को कीट खिलाकर पालने वाली गौरैया जैसी चिड़ियां वापस लौट आयेंगी। इसके व्यापक लाभ होंगे।

किसान का सबसे ज्यादा खर्च समय और सिंचाई के रूप में होता है। नीलगाय, जंगली सुअर आदि जीवों को यदि उनके जंगल, झुरमुट और पेयजल स्त्रोत लौटा दिए जायें तो रखवाली में जाया होने वाला समय स्वतः बच जायेगा। महाराष्ट्र आदि में आज ऐसे इलाके कई हैं, जहां सिंचाई के लिए पानी 750 फीट गहरे से ऊपर लाना होता है। जलसंचयन स्त्रोतों, छोटे बरसाती नालों, नदियों और इनके किनारे झड़ियों–जंगलों के पुनर्जीवित होते ही हम पायेंगे कि भू–जल स्तर स्वतः ऊपर उठ आया। मेड़बंदी ऊंची हो; खेत समतल हो; बूंद–बूंद सिंचाई तथा फव्वारा जैसी अनुशासित सिंचाई पद्धतियां इस्तेमाल हों, तो कम पानी में पूरे खेत में सिंचाई संभव है। स्पष्ट है कि इन कदमों के उठते ही सिंचाई लागत में अप्रत्याशित घटोत्तरी देखने को मिलेगी। इस दिशा में सरकारों के कुछ कार्यक्रम हैं। उनका लाभ सभी तक कैसे पहुंचे; इसके लिए कुछ लोग, पंचायतों को सक्रिय करने में लगें तो कुछ बिना किसी की प्रतीक्षा किए खुद शुरुआत करने में। यह भी भारत के अन्नदाता की रक्षा का एक आंदोलन ही होगा। इसमें हिंसा नहीं, साझा, सहकार और स्वावलंबन फैलेगा। ❑❑

खतरनाक है जीएम फसलों का प्रसार

जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त की गई फसलों का मनुष्यों व सभी जीवों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ सकता है। निष्ठावान वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से जी.ई. फसलों के गंभीर खतरों को बताने वाले दर्जनों अध्ययन उपलब्ध हैं। जैफरी एम. स्मिथ की पुस्तक 'जेनेटिक रुलेट् (जुआ)' के 300 से अधिक पृष्ठों में ऐसे दर्जनों अध्ययनों का सार–संक्षेप या परिचय उपलब्ध है। इनमें चूहों पर हुए अनुसंधानों में पेट, लिवर, आंतों जैसे विभिन्न महत्त्वपूर्ण अंगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की चर्चा है। जी.ई. फसल या उत्पाद खाने वाले पषु–पक्षियों के मरने या बीमार होने की चर्चा है व जेनेटिक उत्पादों से मनुष्यों में भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का वर्णन है।

भोजन की सुरक्षा के लिए कई नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इनके बारे में सामान्य नागरिक को सावधान रहना चाहिए व उपभोक्ता संगठनों को नवीनतम जानकारी नागरिकों तक पहुंचानी चाहिए। पर सबसे जरूरी कदम तो यह उठाना चाहिए कि जीएम फसलों के प्रसार पर कड़ी रोक लगा देनी चाहिए।

– भारत डोगरा

यूनियन आफ कन्सर्नड साईंटिस्टस नामक वैज्ञानिकों के संगठन ने कुछ समय पहले अमेरिका में कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के उत्पादों पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह असुरक्षित हैं। इनसे उपभोक्ताओं, किसानों व पर्यावरण को कई खतरे हैं। इंडिपेंडेंट साईंस पैनल में मौजूद 11 देषों के वैज्ञानिकों ने जी.ई. फसलों के स्वास्थ्य के लिए अनेक संभावित दुष्परिणामों की ओर ध्यान दिलाया है, जैसे– प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल असर, एलर्जी, जन्म विकार, गर्भपात आदि। भारत में सेंटर फार सेल्यूलर और मालीक्यूलर बायलोजी के पूर्व निदेषक प्रो. पुष्प भार्गव ने कहा है कि बीटी बैंगन को स्वीकृति देना एक बड़ी आपदा बुलाने जैसा है।

कुछ समय पहले भारत में बीटी बैंगन के संदर्भ में इस विवाद ने जोर पकड़ा तो विष्व के 17 विख्यात वैज्ञानिकों ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई। पत्र में कहा गया था कि जीएम प्रक्रिया से गुजरने वाले पौधे का जैव–रसायन बुरी तरह अस्त–व्यस्त हो जाता हैं, जिससे उसमें नए विषैले या एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्त्वों का प्रवेष हो सकता है तथा उसके पोषण गुण कम हो सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मक्के की जीएम किस्म 'जीएम एमओएन 810' की तुलना गैर–जीएम मक्का से करें तो इस जीएम मक्का में 40 प्रोटीनों की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हद तक बदल जाती है। जीव–जंतुओं को जीएम खाद्य खिलाने पर आधारित अनेक अध्ययनों से जीएम खाद्य के गुर्दे (किडनी), यकृत (लिवर) पेट व निकट के अंगों (गट), रक्त कोषिका, रक्त जैव रसायन व प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी सिस्टम) पर नकारात्मक स्वास्थ्य असर सामने आ चुके हैं।

17 वैज्ञानिकों के इस पत्र में आगे कहा गया था कि जिन जीएम फसलों को स्वीकृति मिल चुकी है उनके संदर्भ में भी अध्ययनों से यह नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम नजर आए

हैं जिससे पता चलता है कि कितनी अपूर्ण जानकारी के आधार पर स्वीकृति दे दी जाती है व आज भी दी जा रही है।

इन वैज्ञानिकों ने कहा था कि जिन जीव–जंतुओं को बीटी मक्का खिलाया गया तो उनमें प्रत्यक्ष विषैलेपन का प्रभाव देखा गया। बीटी मक्के पर मॉनसैंटो ने अपने अनुसंधान का जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो अल्पकालीन अध्ययन में भी नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम दिखाई दिए। बीटी के विषैलेपन से एलर्जी की रिएक्षन का खतरा जुड़ा हुआ है। बीटी बैंगन जंतुओं को फीड करने के अध्ययनों पर महको–मॉनसेंटो ने जो दस्तावेज तैयार किया, उससे लिवर, किडनी, खून व पैंक्रियास पर नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम, विभिन्न जीव–जंतुओं पर (विषेषकर चूहे, खरगोष व बकरी पर) नजर आते हैं। अल्पकालीन (केवल 90 दिन या उससे भी कम) अध्ययन में भी यह प्रतिकूल परिणाम नजर आए जबकि जीवन–भर के अध्ययन से और भी कितने प्रतिकूल परिणाम सामने आते, इस पर प्रष्न खड़े हो गए हैं। अतः इन वैज्ञानिकों ने कहा था) कि बीटी बैंगन के सुरक्षित होने के दावे का कोई औचित्य नहीं है। यह दावा तो बस इस आधार पर किया जा सका कि महको–मानसेंटो के आंकड़ों की व्याख्या को बिना जांचे–परखे स्वीकार कर लिया गया। थोड़े से भी दीर्घकालीन, कम से कम 2 वर्ष के अध्ययन तो किए ही नहीं गए।

बीटी कपास या उसके अवषेष खाने के बाद या ऐसे खेत में चरने के बाद अनेक भेड़–बकरियों के मरने व अनेक पषुओं के बीमार होने के समाचार मिले हैं। डा. सागरी रामदास ने इस मामले पर विस्तृत अनुसंधान किया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे मामले विषेषकर आंध्र प्रदेष, हरियाणा, कर्नाटक व महाराष्ट्र में सामने आए हैं। परंतु अनुसंधान तंत्र ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया है व इस गंभीर चिंता के विषय को उपेक्षित किया है। भेड़ बकरी चराने वालों ने स्पष्ट बताया कि सामान्य कपास के खेतों में चरने पर ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं पहले नहीं देखी गई थी व जीएम फसल के आने के बाद ही यह समस्याएं देखी गईं। हरियाणा में दुधारू पषुओं को बीटी काटन बीज व खली खिलाने के बाद उनमें दूध कम होने व प्रजनन की गंभीर समस्याएं सामने आईं।

बीटी बैंगन पर रोक लगाते हुए पर्यावरण मंत्री जयराम रमेष ने जो दस्तावेज जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य के खतरे के बारे में उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेषक व भारतीय सरकार के औषधि नियंत्रक से चर्चा की थी। इन दोनों अधिकारियों ने कहा कि विषैलेपन व स्वास्थ्य के खतरे संबंधी स्वतंत्र टैस्ट होने चाहिए। केवल उत्पाद बेचने वाली कंपनी के टैस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

अमेरिका अकादमी ने अपनी संस्तुति में कहा है कि जीएम खाद्य से बहुत खतरे जुड़े हैं व इन पर मनुष्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त परीक्षण नहीं हुए हैं।

लगभग 100 डाक्टरों का एक संगठन है 'खाद्य व सुरक्षा के लिए डाक्टर', इस संगठन ने भी पर्यावरण मंत्री को जीएम खाद्य व विषेषकर बीटी बैंगन के खतरे के बारे में जानकारी भेजी। उनके दस्तावेज में बताया गया कि पारिस्थितिकीय चिकित्सा शास्त्र की अमेरिका अकादमी ने अपनी संस्तुति में कहा है कि जीएम खाद्य से बहुत खतरे जुड़े हैं व इन पर मनुष्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त परीक्षण नहीं हुए हैं।

तीन वैज्ञानिकों में वान हो, हार्टमट मेयर व जो. कमिन्स ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की विफलताओं की पोल खोलते हुए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज इकॉलाजिस्ट पत्रिका में प्रकाषित किया है। इस दस्तावेज के अनुसार बहुचर्चित चमत्कारी 'सूअर' या 'सुपरपिग', जिसके लिए मनुष्य की वृद्वि के हारमोन प्राप्त किए गए थे, बुरी तरह 'फ्लाप' हो चुका है। इस तरह जो सूअर वास्तव में तैयार हुआ उसको अल्सर थे, वह जोड़ों के दर्द से पीड़ित था, अन्धा था और नपुसंक था।

इसी तरह तेजी से बढ़ने वाली मछलियों के जीन्स प्राप्त कर जो सुपरसैलमन मछली तैयार की गई उसका सिर बहुत बड़ा था, वह न तो ठीक से देख सकती थी, न सांस ले सकती थी, न भोजन ग्रहण कर सकती थी व इस कारण शीघ्र ही मर जाती थी।

बहुचर्चित भेड़ डॉली के जो क्लोन तैयार हुए वे असामान्य थे व सामान्य भेड़ के बच्चों की तुलना में जन्म के समय उनकी मृत्यु की संभावना आठ गुणा अधिक पाई गई।

जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन अनुभवों को देखते हुए उससे प्राप्त भोजन को हम कितना सुरक्षित मानेंगे यह सोचने–विचारने का विषय है।

अतः यह स्पष्ट है कि भोजन की सुरक्षा के लिए कई नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इनके बारे में सामान्य नागरिक को सावधान रहना चाहिए व उपभोक्ता संगठनों को नवीनतम जानकारी नागरिकों तक पहुंचानी चाहिए। पर सबसे जरूरी कदम तो यह उठाना चाहिए कि जीएम फसलों के प्रसार पर कड़ी रोक लगा देनी चाहिए। ❑❑

पं. दीनदयाल उपाध्याय

विचारों की मुंदरी का अनगढ़ नगीना

कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहने वाले पंडित जी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार अर्थात् पंडित नेहरु की नीतियों का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उस विरोध के साथ–साथ वैकल्पिक वैचारिक मॉडल भी प्रस्तुत किया।

– आशीष रावत

कहा जाता है कि कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसमें से दूसरी श्रेणी के थे। न तो उन्होंने किसी समृद्ध घर में जन्म लिया था, न उनके पास संपत्ति थी और न उनके पास कोई उच्च पद था। इतने पर भी वे भारतीय राजनीतिज्ञों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। अनेक प्रसिद्ध नेता मृत्यु के बाद विस्मृति के गर्त में समा गए। दीनदयाल जी वास्तव में सच्चे पुरुषों में से थे, जो मृत्यु के बाद और ऊंचे उठते हैं। 25 सितंबर, 1916 को उत्तर प्रदेष के मथुरा में जन्म लेने वाले पंडित दीनदयाल का स्पष्ट मानना था कि समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद व्यक्ति के एकांगी विकास की बात करते हैं जबकि व्यक्ति की समग्र जरूरतों का मूल्यांकन किए बिना कोई भी विचार भारत के विकास के अनुकूल नहीं होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीयता के अनुकूल पूर्ण भारतीय चिंतन के रूप में 'एकात्म मानववाद' का दर्षन प्रस्तुत किया जो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का आदर्ष है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन यात्रा के विविध आयाम हैं। कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहने वाले पंडित जी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार अर्थात् पंडित नेहरु की नीतियों का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उस विरोध के साथ–साथ वैकल्पिक वैचारिक मॉडल भी प्रस्तुत किया। उनके जीवन के अनेक पक्ष, अनेक आयाम और अनेक कार्य हैं जिन पर बहुत चर्चा नहीं हो पाई है।

सन् 1937 में पंडित जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। उत्तर प्रदेष में उस समय संघ का कार्य प्रारंभ ही हो रहा था और इस प्रकार दीनदयाल जी वहां नींव की षिलाओं की भांति सर्वप्रथम बने स्वयंसेवकों में से एक थे। शीघ्र ही भारत के इस सबसे विस्तृत राज्य में संघ को एक समर्थ शक्ति बनाने के कार्य में वे जुट गए। पढ़ाई पूरी कर लेने के साथ ही उन्होंने कोई नौकरी न करने का निष्चय किया। उसके स्थान पर, उन्होंने राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय एकता के संघ कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने का निष्चय कर लिया। 1942 में उत्तर प्रदेष के अंतर्गत लखमीपुर जिला प्रचारक के रूप में कार्यारंभ कर पांच वर्ष के अंदर ही वे सह प्रांत प्रचारक बन गए। इस प्रकार श्री भाऊराव देवरस के बाद उनका ही स्थान था। वे 1951 तक इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद जब उसी वर्ष भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, तब उनकी सेवाएं उन्हें अर्पित कर दी गई और वे उत्तर प्रदेष भारतीय जनसंघ के मंत्री बने। अगले वर्ष जनसंघ के कानपुर अधिवेषन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें भारतीय जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया। डॉ. मुखर्जी

उनकी संगठन क्षमता से इतने अधिक प्रभावित हुए कि कानपुर अधिवेषन के बाद उनके मुंह से यही उद्‌गार निकले कि 'यदि मेरे पास और दो दीनदयाल हों तो मैं भारत का राजनीतिक रूप बदल दूंगा।' दुर्भाग्य से 1953 में डॉ. मुखर्जी की मृत्यु हो गई और भारत के राजनीतिक रूप को बदल देने का दायित्व स्वयं दीनदयाल जी के कंधों पर आ पड़ा। उन्होंने इस कार्य को इतने चुपचाप और विषेष ढंग से पूरा किया कि जब 1967 में आम चुनावों के परिणाम सामने आने लगे तब देष आष्चर्यचकित रह गया। उन्होंने इसे द्वितीय क्रांति की संज्ञा दी भारत की स्वतंत्रता पहली क्रांति थी। जनसंघ राजनीतिक दलों में दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया। यह स्पष्ट हो गया कि उसके पास प्रथम क्रमांक पर पहुंचने में अब कुछ ही वर्ष का समय लगेगा। वे 'स्वदेषी' के बारे में शोर तो नहीं मचाते थे, परंतु वे कभी भी विदेषी वस्तु नहीं खरीदते थे। लखनऊ से प्रकाषित 'पांचजन्य' साप्ताहिक और 'स्वदेष' दैनिक के संपादक के रूप में वे न केवल इन पत्रों को संपादन करते थे, अपितु आवष्यक होने पर कम्पोज भी करते थे, मषीन भी चला लेते थे और 'बाइंडर' तथा 'डिस्पैचर' का कार्य भी कर लेते थे। 1940–49 के बीच एक बार तो उन्होंने एक ही बार में सोलह घंटे बैठकर 'चन्द्रगुप्त मौर्य' नामक लघु उपन्यास लिख डाला। बाद में उन्होंने हिन्दी में ही 'षंकराचार्य' का एक जीवन–चरित्र भी लिखा। तदुपरांत उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के अधिकृत जीवन–चरित्र का मराठी से हिन्दी में अनुवाद किया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दृष्टिकोण सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि रचानात्मक भी था। जिस बिन्दु पर उनका विरोध होता था, उस बिन्दु पर उनके पास विकल्प की दृष्टि भी होती

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दृष्टिकोण सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि रचानात्मक भी था। जिस बिन्दु पर उनका विरोध होता था, उस बिन्दु पर उनके पास विकल्प की दृष्टि भी होती थी।

थी। उन्होंने समाजवाद, मार्क्सवाद और पूंजीवाद को भारतीय दृष्टिकोण के प्रतिकूल मानते हुए अस्वीकार किया तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुकूल "एकात्म मानववाद" का वैचारिक दर्षन भी प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि थी कि मनुष्य को सिर्फ एकांगी होकर "आर्थिक प्राणी" के रूप में देखने से विकास उन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता जिससे राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाया जाए। मनुष्य को इकाई मानकर उसकी समग्र जरूरतों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक का समग्रता में चिंतन करते हुए हमें विकास की प्रक्रिया को चलाना होगा। भारतीय राजनीति में सादगी के कुछ उदाहरणों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। बेहद साधारण जीवन जीने वाले नेता थे। पॉलिटिकल डायरी में लिखा है "दीनदयाल एक महान नेता बन गए थे, परंतु अपने कपड़े स्वयं साफ करते थे"। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कहा है "वे स्वयं संसद सदस्य नहीं थे, परंतु वे जनसंघ के सभी संसद सदस्यों के निर्माता थे। 'मैं' शब्द के प्रयोग को वे निषिद्ध मानते थे।"

राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए शुचिता प्राथमिक थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कार्यकर्ताओं के आग्रह एवं तत्कालीन प्रांत प्रचारक भाऊराव देवरस के कहने पर जौनपुर से चुनाव लड़े। यह वह चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने जातिवाद और भ्रष्टाचार जैसे हथकंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने राजपूतवाद का माहौल तैयार किया तो कुछ जनसंघ कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल जी का नाम लेकर "ब्राह्मण" कार्ड चलने की योजना तैयार की। जब यह बात पंडित जी को पता चली तो वे बुरी तरह बिगड़ गए और फटकार लगाई। वे चुनाव नहीं जीत सके लेकिन अपनी राजनीतिक शुचिता को कभी हारने नहीं दिया। जौनपुर के लोग उस हार को आज भी एक आदर्ष हार की जीत के रूप में याद करते हैं। 11 फरवरी, 1968 को रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी हत्या होने के केवल कुछ सप्ताह पूर्व दीनदयालजी ने जनसंघ के ऐतिहासिक कालीकट अधिवेषन की अध्यक्षता की। उस अधिवेषन के बारे में मत व्यक्त करते हुए भारत के सबसे अधिक प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र 'मातृभूमि' ने लिखा कि 'तीन दिन तक ऐसा प्रतीत हुआ, मानो गंगा ने अपना मार्ग बदल दिया है और उसने केरल होकर बहना आरम्भ कर दिया है।' जनसंघ दक्षिण में एक भारी धमाके के साथ पहुंचा था। उस महान् समय में ही उनकी हत्या कर दी गई। जैसा कि पहले स्वामी दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा गांधी की हत्याएं हुईं थीं। पंडित जी रहस्यमयी हत्या ने असमय उनको हमसे छीन लिया, लेकिन वे जब तक रहे अपने मानदंडों पर जीने वाले सबके प्रिय रहे। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता एवं उत्तर प्रदेष के मुख्यमंत्री रह चुके संपूर्णानंद ने न सिर्फ उनके लेखों के संकलन "पॉलिटिकल डायरी" का प्राक्कथन लिखा है बल्कि उन्हें महान और भविष्य की राजनीति के लिए प्रेरणादायी नेता बताया है। ❑❑

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल

भारत में हिंदी का वहीं महत्व है जो किसी शरीर में आत्मा का होता है। हिंदी उन्नति की ओर अग्रसर है। हिंदी आज विश्व की तीसरी प्रमुख भाषा है। विश्व में यह कई देषों में बोली व समझी जाती है। देखने में लगता है कि अंग्रेजी हिंदी को पछाड़ देगी, परंतु विश्व में दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले मात्र 60 करोड़ लोग है जो मात्र हिंदी (50 करोड़) भाषा से मात्र 10 करोड़ ही ज्यादा है। 96 करोड़ लोग मंदारिन भाषा बोलते है। माना जाता है कि लगभग इतने ही लोग हिंदी को समझते भी है, जिन–जिन देषों में भारत से मजदूर ले जाये गये। हिंदी भारत में राजभाषा व राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव मिला व संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित करके देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बनाया।

हिंदी भाषी लोग व देष प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रुप में मनाने लगे है। परंतु एक लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी हिंदी को राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिल सका है। देष के राजनेता राजनीति करते हुए हिंदी भाषा के नाम पर विभिन्न प्रदेषवासियों को आपस में लडाते रहते है। वर्तमान लोकतांत्रित राजनीतिक व्यवस्था में हिंदी भाषा राजनीति का षिकार हो चुकी है। देष के लगभग सभी प्रमुख नेताओं जैसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, पं. जवाहर लाल नेहरु, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णनन इत्यादि दिग्गजों ने हिंदी को न केवल स्वीकार किया अपितु इसकी सेवा भी की। दक्षिण के कई राज्य थोड़ा भी कहते है व मांग करते है तो सरकार उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए, मान लेती है कि हिंदी को थोपा नहीं

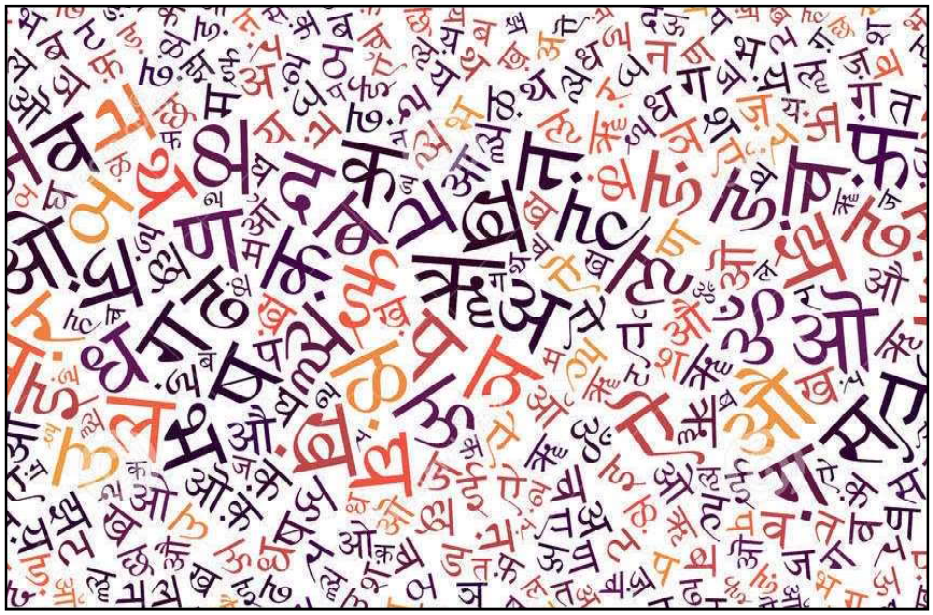

आज भारत व विश्व में हिंदी के प्रति अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो गया है जिससे लगता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

जायेगा। वे राज्य अंग्रेजी को तो स्वीकार कर लेते है परंतु राजनीति के चलते राजभाषा हिंदी को स्वीकार करने में कोताही करते है।

हिंदी को गत 70–72 वर्षों में जो गौरव मिलना चाहिए था वह उसको अभी तक नहीं मिल सका है। मुझे यह कहने में कोई कोताही नहीं है कि हिंदी वर्तमान राजनेताओं की दृष्टि राजनीति का षिकार हो चुकी है तथा अब जानबुझकर हिंदी को बेइज्जत किया जा रहा है। दक्षिण राज्यों में हिंदी के साइन बोर्ड तारकोल से पोते जाते है तथा उन पर स्थानीय व अंग्रेजी भाषा में लिखा जा रहा है जिससे जब अधिसंख्य भाषी लोग उन प्रदेषों में घुमने अथवा अपने किसी काम से जाते है तो उन्हें भारी परेषानी का षिकार होना पड़ता है जिससे उस राज्य के प्रति भी उनके मन में अपनत्व के भाव जागृत नहीं पाते है, विषेषकर अंग्रेजी को देखकर।

भारतीय सिनेमा को हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए साधुवाद दिया जा सकता है जिससे कि हिंदी भाषा संपूर्ण देश में ही गांव-गांव व जन-जन की भाषा बन गई है

भारतीय सिनेमा को हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए साधुवाद दिया जा सकता है जिससे कि हिंदी भाषा संपूर्ण देष में ही गांव–गांव व जन–जन की भाषा बन गई है जो व्यापक रुप से बोली व समझी जाने लगी है। हिंदी भाषा बोली जाने वाले राज्यों में वहां की बोलियां भोजपुरी, अवधि इत्यादि पूर्ण भाषा का दर्जा बनने की मांग करती रहती है।

कुछ देषों में हिंदी को विश्वविद्यालयों में मान्यता देकर उसमें पाठ्यक्रम चलाये जाते है। अमेरिका, जापान, यू.के., फ्रांस, स्पेन, सिंगापुर इत्यादि विकसित देषों में हिंदी की षिक्षा दी जा रही है क्योंकि जो लोग भारत को भली प्रकार समझना चाहते है उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे पहले हिंदी पढें व सीखें तभी वे भारत आकर भारत को भली प्रकार समझ पायेंगें। भारत ने व हिंदी भाषी लोगों ने कभी भी तलवार या शक्ति या हिंसा के दबाब में हिंदी को सिखाने व समझाने के लिए नहीं कहा तथा न ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए कोई आंदोलन चलाया था।

हिंदी को शुद्ध लिखने की कोषिष करनी चाहिए व हिंदी भाषी लोगों से इसकी अपेक्षा भी की जाती है। कोई अहिंदी भाषी यदि कोई गलती कर रहा है तो शालीनता से ठीक कराने की जिम्मेदारी हम हिंदी भाषी लोगों की है। आज भारत में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसमें हम बच्चों की षिक्षा व दीक्षा अंग्रेजी से ही प्रारंभ कराने की कोषिष करते है। बच्चों को जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्दों को बोलने के लिए बल प्रयोग करते है। क्या विकास व उन्नति के लिए हमें अपनी भाषा पर भरोसा नहीं रह गया है। देष में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रादुर्भाव के बढने से अंग्रेजी का सीधा संबंध नौकरी से हो गया है। अंग्रेजी बोलने व लिखने वाले लोग आजकल वास्तविक रुप से बुद्धिजीवी व सभ्य समझे जाते है तथा हिंदी बोलने वाले लोग पिछडे व असभ्य समझे जाते है। अंग्रेजी माध्यम से जबरदस्ती पढाई करने का दबाब का प्रभाव बच्चे के मनोविज्ञान पर पड़ता है। वह ठीक प्रकार से पढ़ाई को समझ ही नहीं पाता है। यदि बच्चे को प्रारंभ से हिंदी में पढ़ाया गया होता तो उसकी समझदारी बढ़ गई होती। अंग्रेजी तो इतनी सरल व आसान है कि 90 दिनों का एक पाठ्यक्रम करने से उसको सीखा व बोला जा सकता है। ऐसे कई विज्ञापन आम तौर पर सडक के किनारे साइन बोर्डों में देखे जा सकते है।

यह ठीक है कि किसी भी भाषा की प्रगति व उन्नति तभी हो सकती है जब उसका सीधा संबंध रोजगार से होता है। अंग्रेजी की उन्नति इसलिए ही हो पायी है कि उसका सीधा संबंध रोजगार से स्थापित हो चुका है। अब यह उम्मीद हो चली है कि यदि हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी पर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या में आषातीत कमी हो जायेगी। संख्या में कमी की रफ्तार तेज होती यदि देष में सिनेमा व टीवी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ होता।

सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेटे हिंदी अब विश्व में अपने पर फैला रही हैं। इंटरनेट के द्वारा इस युग में हिंदी को अब वैश्विक स्तर का सम्मान मिल रहा है तथा इंटरनेट पर हिंदी सामग्री के इस्तेमाल की वृद्धि 94 प्रतिषत दर है। विश्व में वेबसाइटें हिंदी को महत्व दे रही है। ई–मेल, ई–कॉमर्स, ई–बुक, इंटरनेट, एमएमएस एवम् वेब जगत में बडी सहजता से पाया जा सकता है। माइक्रोसाफ्ट, गूगल, सन, याहू, आईबीएम तथा ओरेकल जैसी विश्वस्तरीय कंपनियां व्यापक बाजार व बड़े मुनाफे को देखते हुए हिंदी को बढ़ावा दे रही है। फिजी, मॉरीषस,

गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाट, टौबेगों एवम् संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि में हिंदी अल्पसंख्यक भाषा के रुप में जानी जाती है। विश्व में लगभग 115 षिक्षण संस्थाओं में हिंदी का अध्ययन होता है। अमरीका में 32 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। यू.के. में लंदन, कैंब्रिज और यार्क विश्वविद्याालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। जर्मनी में भी कई संगठन हिंदी का प्रचार व प्रसार करते है तथा 15 षिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा व साहित्य का अध्ययन होता है। चीन में भी 1942 से हिंदी का पठन पाठन शुरु हुआ था तथा 1957 से हिंदी रचनाओं का चीनी अनुवाद शुरु हुआ था।

भारत में देषी व विदेषी कंपनियों में अंग्रेजी का बोलबाला है। परंतु हिंदी को भी सम्मान मिलता है। अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होते हुए भी हिंदी जानने वालों के लिए खास जगह व तरक्की के सुनहरे अवसर मौजूद रहते है। जनसंपर्क कंपनियां ही कॉरपोरेट कम्युनिकेषन का काम करती है। 2016 में जनसंपर्क कंपनियों का 1,120 करोड रुपये का करोबार अनुमानित था। यह कारोबार 2020 तक 2,100 करोड रुपये होने की आषा है। अखबार, पत्रिकायें, रेडियों, टी.वी., सिनेमा, कम्पूटर, होर्डिंग व मोबाइल के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। विज्ञापन दुनिया में हिंदी विज्ञापनों और जिंगल्स का हो गया है।

आज विश्व में औसत रुप से 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी को समझ लेता है। हिंदी की वैश्विकता के चलते ललितकला के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी वैश्विक हो चली है। ऑनलाइन और ई–बुक्स के समय में लेखन रोजी–रोटी से जुड़ गया है। गायक अभिनय भाषा का मोहताज नहीं होता परंतु वाचिक अभिनय में भाषा का अच्छा ज्ञान अभिनेता व अभिनेत्री को दर्षकों के दिल के अंदर जाने का अवसर देता है। आर्थिक उदारीकरण ने हिंदी अनुवाद बाजार को हवा दी है। भारत का बाजार विदेषी कंपनियों के लिए खुला तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत एक विस्तृत व बड़ा बाजार दिखाई दिया। इस बाजार में पैठ बनाने के लिए हिंदी उन कंपनियों के लिए अनिवार्य हो गई है। विदेषी भाषाओं के कई प्रकाषक – पेंगुइन, हार्पर कालिंग्स और पियरसन जैसे दिग्गज प्रकाषक भी हिंदी बाजार में आ गये है।

ऑनलाइन हिंदी षिक्षण के कई पाठ्यक्रम स्वरोजगार की दिषा में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास कर रहे है। संचार– सूचना प्रौद्योगिकी में दिनोंदिन बढ़ रही हिंदी की उपयोगिता और अनिवार्यता अधिक से अधिक कार्य सक्षम युवाओं को रोजगार दिला रही है। ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग और विकीपीढ़िया के लिए हिंदी में लेखन सृजनात्मक संतुष्टि के साथ वित्तीय लाभ का अवसर भी उपलब्ध हो रहा है। यूनिकोड के आने से अब हिंदी में टाइप करना और भी आसान हो गया है।

हिंदी दिवस पर हिंदी के उत्थान के लिए गोष्ठियां व चर्चा हुई। नतीजा यहीं निकला कि हिंदी को प्रोत्साहन तभी मिल सकेगा जब यह रोजगार के साथ जुड़ जाये, अब हिंदी सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रही है। प्रौद्योगिकी से लेकर रोजगार देने वाली नए दौर की तमाम रचनात्मक विद्याओं में आज हिंदी का बोलबाला है इसलिए अंग्रेजी के साथ हिंदी जानने वाले लोग भी अभिमान के साथ कह रहे हैं कि हिंदी है हम, हम में है दम। भारत से बाहर 260 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है जिनमें यू.के. के 67 तथा चीन के 20 विश्वविद्यालय शामिल है। इन विश्वविद्यालयों में न केवल प्रवासी भारतीय अपितु विदेषी छात्र भी स्नातक से लेकर पीएचडी तक षिक्षा ग्रहण कर रहे है।

आज भारत व विश्व में हिंदी के प्रति अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो गया है जिससे लगता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। हम केवल इतना कर सकते है कि अपने घर, परिवार में अधिक से अधिक हिंदी बोलें, बच्चों के साथ हिंदी ही बोलें, अपने चारों ओर फैले लोगों जैसे अखबार वाला, सब्जीवाला, किराना दुकानदार इत्यादि से हिंदी में बात करें और यदि कोई कटाक्ष करता है तो करने दें। बलात् अंग्रेजी बोलने, लिखने से बेहतर है कि सही हिंदी बोलें व लिखें। पत्राचार हिंदी में करें। हिंदी को रोजगार से जोड़ने वाले पाठयक्रम करें जैसे अनुवादक इत्यादि के पाठयक्रम करें। हिंदी को बोलते लिखते समय स्वयं को उपेक्षित, अपमानित व हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। स्वयं को सकारात्मक सोच के साथ सम्मानित महसूस करें। ❑❑

भारत से बाहर 260 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है जिनमें यू.के. के 67 तथा चीन के 20 विश्वविद्यालय शामिल है।

लेखक प्रावार्य, ताराचंद वैदिक पुत्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर में प्राचार्य है।

उद्योगोन्मुख शिक्षाः राष्ट्रीय विकास का आधार

लघु एवं कुटीर उद्योग सदैव भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर सन् 1800 तक भारत वैष्विक व्यापार में संपन्न अग्रणी देष था। भारतीय व्यापारी पूर्व स्थित देषों (थाईलैंड, कंबोडिया, हिन्देषिया) तथा पष्चिम में स्थित (अरब, फारस, मिश्र, रोम, यूनान) देषों के साथ सूती वस्त्र, रेषमी वस्त्रों, मसालों, हस्तनिर्मित कलाओं, बहुमूल्य पत्थरों, चाँदी, सोना व अन्य धातुओं का व्यापार करते थे। औपनिवेषिक साम्राज्य के विस्तार से पूर्व पूरे देष की अर्थव्यवस्था स्थानीय कुटीर एवं लघु उद्योगों पर आधारित थी।

ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देषों के औद्योगिक विकास के लिये औपनिवेषिक देषों की प्राकृतिक संपदा और संसाधन उपलब्ध हो सके, इसके लिए सन् 1813 के **चार्टर एक्ट** के तहत इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इससे भारत सहित सभी एषियाई औपनिवेषिक देषों में संपदा संरक्षण के पुराने नियम स्वतः समाप्त हो गये। विभिन्न कानूनों की आड़ में ब्रिटिष सरकार द्वारा लगभग 150 वर्षों तक भारत के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन किया जाता रहा। ब्रिटिष शासन द्वारा षडयंत्रपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योग नष्ट कर दिये गये। भारत की उत्पादन शक्ति समाप्त होने से सूती–वस्त्रों जैसी बुनियादी आवष्यकता के लिये भी हम यूरोपीय देषों पर निर्भर हो गये। औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिये भारत से कच्चामाल यूरोपीय देषों को जाता रहा और वहाँ के उद्योगों से निर्मित माल भारतीय बाजारों में खपाया जाता रहा। इस व्यवस्था के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी रहे सभी कुटीर उद्योग धीरे–धीरे स्वतः नष्ट होते चले गये।

भारत में उद्योग चलाने के लिये अंग्रेजों द्वारा भारत के बड़े व्यापारिक केन्द्रों– कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुम्बई में इंग्लैंड से आयातित नवीन मषीनरी स्थापित की गई। ये मषीनें

उद्योगोन्मुख शिक्षा द्वारा स्वरोजगार व उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे तथा औद्योगिक विकास द्वारा देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी तो भारत पुनः अपने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

– डॉ. रेखा भट्ट

भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था देने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकल्प नहीं बन सकी। मैकॉले द्वारा विद्वेषपूर्ण तरीके से, विष्व की श्रेष्ठ भारतीय षिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देष्य से जो षिक्षा व्यवस्था प्रदान की गई, उससे उद्यमियों तथा दक्ष व हुनरमंद कामगरों के स्थान पर कारखानों व मीलों में काम करने वाले श्रमिक ही प्राप्त हो सकते थे। इस मैकॉलयी षिक्षण व्यवस्था को भारतीय जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए ब्रिटिष कार्यालयों में कर्मचारियों व लिपिकों के रूप में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था दी गई।

आज भी मैकॉले पद्धति पर आधारित षिक्षण व्यवस्था का देष की भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों से कोई सामंजस्य नहीं है। देष की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उष्ण व शुष्क जलवायु की भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल प्राथमिक षिक्षा में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी की 'रेन–रेन गो अवे' जैसी राइम्स तथा अंग्रेजी में गणित के हिसाब किताब में असमर्थ छात्र, षिक्षा की उपयोगिता को समझने में अक्षम रहते हैं।

वर्तमान में देष के औद्योगिक उत्पादन में खनिजों का 11 प्रतिषत योगदान है। देष में लगभग सभी महत्त्वपूर्ण व आधारभूत खनिजों यथा लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, पैट्रोल की उपस्थिति है। भूमिगत एवं भूतल जलसंसाधनों की प्रचुरता है। यहाँ उष्टकटिबंधीय से लेकर शीतोष्ण कटिबंधों की फसलों का उत्पादन होता है। देष में कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन व वनस्पति आधारित पषु आधारित सभी प्रकार के उद्योंगों का समुचित विकास संभव है।

देष के कई जिलों में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद औद्योगिक विकास शून्य है। राज्यों के अंतर्गत जिलों में स्थापित सैकड़ों औद्योगिक इकाइयाँ भी पर्याप्त निवेष की कमी, देख–रेख एवं प्रषिक्षित कुषल कामगारों के अभाव में रूग्णावस्था में चल रही है। राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों में षिक्षण प्रषिक्षण हेतु स्थापित प्रौद्योगिकी षिक्षण संस्थान (आईटीआई) बहुत कम हैं। उनमें स्थानीय उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण **मेड बाई इंडिया अथवा मेक इन इंडिया** एवं **स्किल इंडिया** जैसी योजनाएँ प्रभावी ढंग से फलीभूत नहीं हो पा रही है।

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32 करोड़ 88 लाख हैक्टयर है। देष के भूमि उपयोग में कृषि की प्रधानता है।

खेती की उन्नत तकनीक व उपज बढ़ाने के तरीके विकसित होने के बाद भी आज देश में कृषि शिक्षा उपेक्षित है। भारत में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों का लाभ केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक 5–10 प्रतिशत छात्र ही उठा पाते है।

कृषिगत भूमि का क्षेत्रफल 14.08 करोड़ हैक्टयर है अर्थात् देष की कुल भूमि के 46.04 प्रतिषत भू–भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। भारत चीन की अपेक्षा कृषिगत भूमि का अधिक क्षेत्रफल रखता है। चीन में विष्व की कृषिगत भूमि का 7.1 प्रतिषत भू–भाग (9.75 करोड़ हैक्टयर) है जबकि भारत में विष्व की कुल कृषिगत भूमि का 12 प्रतिषत है। वर्तमान में देष की 22.74 प्रतिषत भूमि पर वनों का विस्तार है।

भारत में कृषि एवं पषुपालन के कार्यों में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता रहती है। पारिवारिक सहयोग के नाम पर बालिका षिक्षा को समाज द्वारा नकार दिया जाता है। कृषि को देष में उद्योग के रूप में सम्मिलित करते हुए प्राथमिक षिक्षा से ही षिक्षण में कृषि विषय को प्रधानता देनी चाहिए। इससे देष की ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिये षिक्षा का पारिवारिक व सामाजिक वातावरण बनेगा जो बालिका षिक्षा को बढ़ावा देने में विषेष रूप से प्रभावी होगा। षिक्षा के अभाव में आज भी ग्रामीण विद्यार्थी अच्छे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। वर्ष 2015 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.4 प्रतिषत रहा। भारत के प्रमुख उद्योग चीनी, जूट, सूती वस्त्र, वनस्पति व बागान उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अनेक लघु व कुटिर उद्योग, हथकरघा, बुनाई, वनस्पति तेल को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि इन सबके विकास पर निर्भर करती है। अंर्तदेषीय मत्स्योत्पादन में भारत का विष्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है विष्व बाजार में भारत की भागीदारी 6 प्रतिषत है। यह देष के 150 लाख लोगों को रोजगार दे रहा हैं।

खेती की उन्नत तकनीक व उपज बढ़ाने के तरीके विकसित होने के बाद भी आज देष में कृषि षिक्षा उपेक्षित है। भारत में स्थापित कृषि विष्वविद्यालयों का लाभ केवल उच्च षिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक 5–10 प्रतिषत छात्र ही उठा पाते है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी व प्रबंधन के सीमित निजी व सरकारी संस्थाओं में, संपन्न एवं अत्यंत प्रतिभाषाली छात्र ही प्रवेष ले पाते हैं। शेष विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े वर्ग के लिये उच्च षिक्षा उनकी पहुंच के बाहर बनी रहती है। षिक्षा संस्थानों द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न कराना, उद्यमिता द्वारा आय के स्रोत एवं नये स्टार्ट अप निर्मित करना, कम लागत में उत्पादन की नवीन तकनीकें खोजना, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साधन व ऊर्जा के नये विकल्प देना जैसे आउटकम विद्यार्थियों को इन

संस्थानों में षिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। षिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय, कक्षा–कक्षीय संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो तभी डिजीटल षिक्षा, इंटरनेट सुविधा, वर्चुअल क्लासरूम तथा आदर्ष विद्यालय बनाने जैसे सरकारी प्रयास सार्थक हो सकेंगे। मध्यांतर भोजन की व्यवस्था करने की अपेक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्किल डवलपमेंट, अंत्रेप्रेंयोरषिप, वोकेषनल ट्रेनिंग के लिये साधन सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायें तो उनमें स्वतः भरण–पोषण करने की योग्यता निर्मित हो सकेगी। षिक्षा की अनिवार्यता जैसे नियमों को, षिक्षा की व्यवहारिकता एवं उपादेयता द्वारा ही साकार किया जा सकता है।

भारत में प्रचलित वर्तमान षिक्षा पद्धति में परंपरागत उद्योगों का आधुनिकीकरण व नवीनीकरण कर उद्योगोन्मुख षिक्षा का ढाँचा विकसित होने पर ही यहां की खनिज संपदा व संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार बन सकेगी। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिये अच्छा निवेष जितना आवष्यक, उसके सफल संचालन के लिये अच्छे प्रबंधक तथा प्रषिक्षित एवं दक्ष कामकागर उतने ही महत्वपूर्ण है। हस्तकला, हस्तषिल्प व हथकरधा जैसे परंपरागत उत्पादन के माध्यमों से व्यापक स्तर पर उत्पादों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः स्थानीय उद्योगों से जुड़े षिक्षण–प्रषिक्षण केंद्र, व्यवसायिक प्रषिक्षण संस्थान व शोध संस्थान स्थापित करने की आवष्यकता है। जिससे औद्योगिक इकाइयों की उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ेगी और भारत में औद्योगिक विनिर्माण को मजबूती मिलेगी।

देष में खनिज संपदा के अतिरिक्त विनिर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण उत्पादों, धातु, जूट, कॉटन, चीनी, ईंधन आदि के उत्पादन की अपार क्षमता है। ग्रामीण संसाधनों व उद्योगों को षिक्षा द्वारा समुन्नत करके भारत को विनिर्माण केंद्र (manufacturring hub) के रूप में विकसित किया जा सकता है। उद्योगोन्मुख षिक्षा द्वारा यहां कम एवं मध्यम आय वर्ग के रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी तथा राज्यों का आर्थिक–सामाजिक विकास होगा।

भारत में व्यावसायिक ऊर्जा (कोयला, पेट्रोल व विद्युत) की प्रति व्यक्ति खपत विष्व के औसत का मात्र आठवां हिस्सा है। ऊर्जा संकट के कारण हर क्षेत्र में उत्पादकता घटी है। गैर परंपरागत साधनों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है।

भारत के गांवों में मध्यम एवं भारी उद्योगों के साथ घर–घर में लघु उद्योगों के विकास से राज्य को आर्थिक रूप में सुदृढ़ बनाया जा सकता है। देष में कम खर्च में उत्पादों का निर्माण कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। नीतियां तय होते ही उन्हें उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए। सरकार के स्तर पर आधुनिकतम तकनीक में प्रषिक्षित कर्मचारियों, इंजीनियरों, प्रबंधकों की नियुक्ति, उद्योगों के लिये स्थान उपलब्ध करवाने, निवेष करने तथा आधारभूत ढाँचा स्थापित करने की आवष्यकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, वहीं उद्योग अबाध्य रूप से चलते रहेंगे, इससे गांवों में सड़कें, यातायात, अस्पताल, व्यावसायिक कार्यालय, शहरों की तरह विकसित किये जा रहे हैं। कारखानों के लिये पानी एवं बिजली के प्रबंध प्रत्येक क्षेत्र में करने की आवष्यकता है।

भारत में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधन को पर्याप्त निवेष एवं षिक्षा द्वारा सही दिषा में क्रियान्वित किया जाये तो उद्योगों में आने वाली समस्याओं जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तथा मार्केटिंग का सरलता से सामना किया जा सकता है। उद्योगोन्मुख षिक्षा द्वारा स्वरोजगार व उद्यमिता के अवसर बढ़ेगे तथा औद्योगिक विकास द्वारा देष की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी तो भारत पुनः अपने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने में सक्षम होगा। ❑❑

लेखक राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में रसायन विज्ञान की व्याख्याता है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

जैविक आहार - व्यवहार

गतांक से आगे...

रासायनिक खाद और कीटनाशक के दुष्प्रभाव

रासायनिक खाद और कीटनाषकों ने अपने अवतरण के साथ ही धरती माता, हवा, जल, मानव शरीर और जड़–चेतन पर विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर दिए थे। मिट्टी, हवा, पानी और प्राणी जगत को धीरे–धीरे अपने विषाक्त प्रभावों में जकड़ते हुए अब तमाम हदों को पार कर लिया है। वास्तव में प्रकृति के सभी घटक एक हद तक भगवान शंकर की तरह विष पीने में सक्षम हैं। वह सीमा अब टूट चुकी है।

मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण अपने चरमोत्कर्ष पर है। रोगकारक कीटाणुओं और मच्छर जैसे कीटों में जो म्यूटेषन हुए हैं, उनकी वजह से रोगों में प्रचलित दवाओं के कम प्रभावी होने की बात चिकित्सा वैज्ञानिक स्वीकारने लगे हैं।

मृदा प्रदूषणः इन रसायनों से मिट्टी प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा फजीहत किसानों की हो रही है, जमीन बंजर होने लगी है। कीटनाषकों के कारण जमीन के मित्र कीटों और जीवाणुओं का भी नाष हो जाता है। परिणामस्वरूप मिट्टी की नेचुरल इकोलॉजी असंतुलित हो जाती है। दरअसल किसानों को यह भी नहीं मालूम है कि दवा की कितनी मात्रा छिड़कने से काम बन सकता है और यह भी नहीं जानते हैं कि यह दवा सांस के साथ शरीर में घुसकर जान भी ले सकती है।

जल प्रदूषणः ये जानलेवा रसायन बरसात के समय पानी के साथ बहकर हमारे जल स्रोतों में घुलमिलकर उन्हें विषमय बना डालते हैं और जल जीवों के अस्तित्व पर खतरे की तरह मंडराने लगते हैं। इस तरह यह जल पीने लायक नहीं रहता।

वायु प्रदूषणः वायुमंडल में कार्बनडाईऑक्साईड का प्राकृतिक संतुलन, जो कि पिछले एक करोड़ साल से स्थिर था पिछले सौ वर्षों में 15 प्रतिषत बढ़ गया है। हर साल लगभग 1.5 करोड़ टन नाईट्रोजन पृथ्वी के जलस्थल में जुड़ती जा रही है। इसी तरह फास्फेट और गंधकीर गैसें भी खाद के कारखानों से निकलकर वातावरण को प्रभावित कर रही हैं।

जड़ चेतन भी मुक्त नहीं: पंतनगर कृषि विष्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक डीडीटी, गैमेक्सीन, डाईएल्डरीन, हैप्टाक्लोर और एल्डरीन की हानिकारक मात्रा मिट्टी, जल, सब्जी, अनाज, बीज, मसाले, दाल, दूध, मक्खन, घी, मानव, वसा, मानव रक्त, मानव दूध, अंडे–मांस और मछलियों में पाई गई है। इनकी सांद्रता (कांट्रेषन) भारतीयों में विष्व के अन्य देष के मुकाबले 15 गुना अधिक पाई गई है। कीटनाषकों के दुष्प्रभाव को कम (खत्म नहीं) करने के लिए सब्जियों को बहते पाने में दो घंटे तक डुबाकर रखना चाहिए।

आखिर ऐसा क्यों हुआ है?: गोबर जैसी निरापद खाद को खेतों से बाहर कर

जैविक खाद और कीटनाशकों से अपनी माटी का अभिषेक कर उसकी पवित्रता की पुनर्प्रतिष्ठा करनी होगी। इसी के तहत हम सब जैविक आहार के पक्ष में अपने प्रयासों को गति दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है।

– डॉ. विजय वशिष्ठ

जहरीली रासायनिक खाद का साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना बेहतर होगा, क्योंकि कारण जानने पर निवारण आसान होता है। हमारे पराभव की शुरूआत संभवतः मध्यकाल में हुई। हमने अपने विष्वगुरूत्व स्वरूप को भुला दिया। अपने धर्मग्रंथों, मान्यताओं और रीति–रिवाजों को हमने अंधविष्वास कहना शुरू कर दिया। आत्म–विस्मरण के इसी दौर में हम गुलाम बन गए। इसी दौर में हमने प्रकृति की उपेक्षा शुरू की थी।

हम यह भी भूल गए कि हमारे पूर्ण अवतार भगवान श्रीकृष्ण ने गायों का महत्व प्रतिपादित करने के लिए गोपाल और गोवर्द्धन बनना स्वीकार किया। भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराने का शास्त्रोक्त विधान इसलिए है क्योंकि गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गो दही और गोधृत के गुण बहुआयामी और कल्पनातीत हैं। परंतु हमने गोमाता को भुला दिया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गाय की बात करना पिछड़ापन माना जाने लगा है। भारतीयता के खिलाफ बात करने वाले आधुनिक और विकासवादी कहलाते हैं।

यत्र–तत्र–सर्वत्र, गाय ही गाय है: वृहतपराषरपुराण, पद्मपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मपुराण, स्कंदपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण, वाल्मीकी रामायण, तुलसी रामायण, रघुवंषपुराण, गवोपनिषद, विष्णु गर्मोतर पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में गाय की महत्ता का विषद वर्णन किया गया है।

गोविंद, गोपाल या गोवर्धन को तो गाय प्रिय है ही, भगवान षिव का वाहन वृषभ है। मृत्युदेवता यमराज के वाहन की अपेक्षा हमें गोमाता और बैल को अपनाना चाहिए। नए युग के हमारे पथ प्रदर्षक पाष्चात्य वैज्ञानिक गाय के विषय में क्या कहते हैं, उस पर एक निगाह डालें।

ऑस्ट्रिया के बायोडायनामिस्ट डॉ. रूडोल्फ स्टेनर ने वेद और उपनिषदों में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विषेष पर आधारित विद्या के जरिए ऐसे सफल नुस्खों का प्रतिपादन किया है, जिनके द्वारा किसान स्वस्थ भूमि प्राप्त कर स्वस्थ पौधे उत्पन्न कर सके, जो मनुष्यों एवं पषुओं के लिए पौष्टिक तथा अधिक खाद्यान पैदा कर सकें।

डॉ. स्टेनर ने ऐसे अनेक नुस्खे प्रतिपादित किए हैं। नुस्खा नं. 500 के तहत प्राकृतिक रूप से या बीमारी की वजह से मरी हुई गाय के सींग में दूध देने वाली गाय का गोबर भर दिया जाता है। शरद ऋतु यानि सितंबर–अक्टूबर के दिनों में शुक्ल पक्ष के समय भूमि में डेढ़ फीट की गहराई में उसे गाढ़ देते हैं। छः माह बाद शुक्ल पक्ष के समय सींग को निकाल लेते हैं। सींग में जो खाद तैयार होती है, उसकी 30 ग्राम मात्रा को 13 लीटर पानी में मिलाकर एक घंटे तक बारी–बारी से क्लॉक वाईज और एंटी क्लॉक वाईज घुमाया जाता है। एक एकड़ कृषि भूमि में बुआई के पहले और दो बार बुआई के बाद डाला गया यह गोबर, खाद और कीटनाषक दोनों का काम बखूबी करता है। इस खाद से प्राप्त फल–सब्जी, अनाज की पौष्टिकता 25 से 40 प्रतिषत ज्यादा हाती है तथा पैदावार भी 30 से 40 प्रतिषत ज्यादा होती है।

हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गाय की बात करना पिछड़ापन माना जाने लगा है। भारतीयता के खिलाफ बात करने वाले आधुनिक और विकासवादी कहलाते हैं।

यह जानकर आष्चर्य होगा कि डॉ. स्टेनर के तमाम नुस्खे तथा श्री बसंत परांजपे के कृषि अग्निहोत्र को आस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया तथा जर्मनी में बाकायदा पढ़ाया जाता है। श्री परांजये के अग्निहोत्र का दक्षिण अमेरिका में काफी प्रचलन है। शर्मनाक बात यह है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आस्ट्रिया के कृषि वैज्ञानिक हमारे कृषि वैज्ञानिकों को वेद वर्णित तरीके समझाने के लिए भारत का दौरा करते हैं।

न्यूजीलैंड के बायोडायनामिस्ट श्री पीटर प्रोक्टर इस सिलसिले में दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, पंतनगर और जबलपुर के कृषि संस्थानों में आयोजित कार्यषालाओं में संबोधित करने आ चुके हैं।

जहां तक रासायनिक खाद और कीटनाषकों का सवाल है 1989 के अगस्त माह में अमेरिका की नेषनल एकेडमी ऑफ साइंस ने प्राकृतिक कृषि का जोरदार समर्थन करते हुए अमेरिका सरकार से इस संदर्भ में अपील की थी।

हमारे देष में मानव पुरूषार्थ के चार चरण बताए गए हैं– धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात् पहले धर्म की षिक्षा मिले– कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। कौन–सा रास्ता सुख एवं आनन्द देगा और कौन–सा दुःख एवं असंतोष का कारक बनेगा। धर्म के इस मूल को समझने के बाद युवक अर्थ यानी धन कमाने के मार्ग पर गतिमान हो और फिर अपनी समस्त कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अन्ततः मोक्ष के मार्ग पर प्रषस्त हो।

अंग्रेजों के संपर्क में आकर हमने इन चरणों का क्रम अदल दिया, पहला चरण अर्थ हो गया। इससे बहुत अनर्थ हुआ है। नैतिक और अनैतिक की सीमाएं टूट गईं। हमने धर्म के इस मूल को छोड़ दिया कि दूसरों का अहित कर

कमाया गया धन सुविधा तो दे सकता है मगर सुख शांति नहीं। यही वजह है कि धन कमाना हमारा एक मात्र अभीष्ट हो गया है।

धन के बाद काम और उसके बाद तीसरे क्रम पर हमने धर्म को पहुंचा दिया है। तीसरे क्रम पर पहुंचने के बाद धर्म की क्या स्थित हुई है, इसका एक ही उदाहरण हमारे धार्मिक स्तर का पूरा–पूरा प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रपट के मुताबिक हरिद्वार नामक तीर्थ में प्रातः स्मरणीया, पापनाषिनी, पुण्य श्लोका गंगा मैय्या को पौने दो करोड़ लीटर मलयुक्त जल प्रतिदिन प्राप्त होता है।

मंदिरों, धर्मषालाओं आदि के लिए दिए गए दान को धर्म कहने वाले हम भारतीयों को घी में गाय की चर्बी मिलाने में कोई झिझक या शर्म नहीं है। अहिंसा को परमधर्म कहने वाले लोग कत्लखानों के सहभागी बने हैं।

क्या कोई रास्ता नहीं है?

एकमात्र रास्ता है हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। जैविक खाद और जैविक कीटनाषक हमारी स्वर्ग–सी भूमि की नैसर्गिकता को लौटा सकते हैं। सुबह का भूला शाम को लौटे तो ही बात बन सकती है। हमें यह प्रण करना होगा कि जहां तक संभव होगा जैविक आहार ही लेंगे। वैसे एक बात को अच्छी तरह से जेहन में बिठा लेना चाहिए कि जब भी आपका पेट, लीवर, फेफड़ा या हृदय किसी बीमारी की गिरफ्त में आता है, तो डॉक्टर सादे भोजन का सुझाव देते हैं। गरिष्ठ भोजन, तली सामग्री, अधिक घी, शक्कर और मावेदार वस्तुएं, खट्टी चीजें, बेसन के व्यंजन, अंडा, मांस, मछली आदि से परहेज के लिए निर्देषित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि शरीर ऐसे भोजन से दुष्प्रभावित होता है। सच यह है कि सादे भोजन से ही हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।

डॉक्टरों की भूमिकाः चूंकि रासायनिक खाद और कीटनाषक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है साथ ही इनके कारण रोगी की परेषानियां एवं शारीरिक लक्षण भ्रमित करने वाले होते हैं। इसके षिक्षा के मद्देनजर डॉक्टरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे अहम बात है कि समाज में डॉक्टर की सलाह को पूरी तवज्जो दी जाती है। यदि पूरा समुदाय जैविक आहार के पक्ष में माहौल बनाए तो देष का स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, साथी ही गांधीजी की ग्रामीण संपन्नता का स्वप्न भी पूरा हो सकेगा। देष को ऊर्जावान, स्वस्थ और उत्साह से भरे नागरिकों की क्षमता तथा दक्षता का पूरा लाभ भी मिलेगा।

मंदिरों, धर्मशालाओं आदि के लिए दिए गए दान को धर्म कहने वाले हम भारतीयों को घी में गाय की चर्बी मिलाने में कोई झिझक या शर्म नहीं है। अहिंसा को परमधर्म कहने वाले लोग कत्लखानों के सहभागी बने हैं।

क्या जैविक आहार की पूर्ति हो सकेगी?

यह प्रष्न स्वाभाविक है आज के इस संक्रमण काल में जैविक आहार कैसे प्राप्त होगा। व्यापार की यह नीति है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति हो जाती है। अतः मांग के अनुरूप जैविक आहार भी समय के साथ–साथ उपलब्ध हो सकेगा। हम इस शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक और निरापद आहार के लिए 10–15 प्रतिषत ज्यादा मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहें तो भारत के किसान इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।

जैविक आहार महंगा क्यों खरीदें?

यह बिल्कुल सच है कि रिडक्षन सेल के इस जमाने में अधिक कीमत देना कोई भी नहीं चाहता है, परंतु जैविक आहार के कारण कई किस्म की कष्टकारक बीमारियों से व्यक्ति बचेगा, ऐसी बीमारियों की जांच व उपचार में हजारों–लाखों रूपये के खर्च और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कष्टों व तकलीफों से भी व्यक्ति बच सकेगा। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सुविधायें दी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री का भी उन्हें इस हेतु संपूर्ण सहयोग प्राप्त है। अखिल भारतीय स्तर पर भी भारत सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

आओ अन्नपूर्णा धरती माता का जैविक खाद से अभिषेक करें

जैविक खाद का एक अर्थ यह भी है कि किसान को खाद के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वह अपने ही खेत के एक छोटे से हिस्से में पहले की तरह जैविक खाद का उत्पादन कर सके। याद रखिए, राष्ट्रीय विकास के लिए गांव का और किसान का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है।

धरती माँ की कोख में तेजाब डालकर हमने अपने जीवन को नरक बना डाला है। मां को बांझ बताकर हम सुख, चैन, प्रसन्नता एवं निरोग होने की अपेक्षा कर रहे हैं। आज गरीब, अमीर सभी किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, क्योंकि हमने प्रकृति से नाता तोड़ लिया है तथा उससे दूर हो चले हैं। आओ अब लौट चलें के पावन उद्घोषण के साथ हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। जैविक खाद और कीटनाषकों से अपनी माटी का अभिषेक कर उसकी पवित्रता की पुनर्प्रतिष्ठा करना होगा। इसी तथ्य के तहत हम सब जैविक आहार के पक्ष में अपने प्रयासों को गति दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ❑❑

दैनिक जागरण

September 7, 2017

चीनी उत्पादों के खिलाफ वैश्विक सहमति बना रहा स्वदेशी जागरण मंच

डोकलाम विवाद के पटाक्षेप के बाद भी स्वदेशी जागरण मंच चीनी उत्पादों के खिलाफ अभियान चलाते हुए इसपर वैश्विक सहमति बना रहा है। इसके लिए चीन से पीड़ित उसके पड़ोसी देशों के अलावा चीनी उत्पादों के प्रभाव से अपना लघु व मध्यम उद्योग गंवा चुके देशों को भी साथ लाया जा रहा है।

असल में चीनी उत्पादों के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है।

इसका समापन 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में विशाल रैली के माध्यम से होगा। मंच की कोशिश है कि इस विरोध रैली में दूसरे देश के नागरिक भी शामिल हों। इसके लिए दिल्ली में मौजूद विभिन्न देशों के राजनयिकों से मुलाकात के साथ दूसरे देशों के उद्यमी, मजदूर व पर्यावरण संगठनों के पदाधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान से नाराज बलूचिस्तान के नागरिक, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफ्रीकी देश हैं, जिनके सूक्ष्म व लघु उद्योग चीन के सस्ते उत्पादों से दम तोड़ रहे हैं और वहां भी चीन के उत्पादों के खिलाफ इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं। इसी तरह वियतनाम, दक्षिण कोरिया व जापान जैसे चीन के पड़ोसी देश हैं, जो चीन की महत्वकांक्षा से सांसत में हैं। इस वैश्विक अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व विभाग से भी मदद मिल रही है। विश्व विभाग का करीब 75 देशों में नेटवर्क है। इस नेटवर्क के माध्यम अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले भारतवंशियों से भी चीनी उत्पादों के बहिष्कार का माहौल तैयार किया जा रहा है।

दैनिक भास्कर

September 17, 2017

स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी वस्तु के बहिष्कार में बनाई मानव श्रृंखला बनाई

रायगढ़: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर शनिवार की सुबह 10 बजे रायगढ़ में चीनी वस्तु के बहिष्कार के लिए स्वदेशी जागरण मंच के बैनर स्टेशन चौक से लेकर घड़ी चौक तक एक मानव श्रृंखला बनाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुमित मिश्रा ने बताया कि इस मानव श्रृंखला में शहर के गणमान्य नागरिक सहित छात्र–छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए।

दैनिक भास्कर

September 29, 2017

स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी सामान की जलाई होली

स्वदेशी जागरण मंच की और से चीनी सामान के विरोध में सिनेमा चौराहे पर गुरुवार शाम को होली जलाई गई। इस मौके पर तेजप्रकाश महावर ने संबोधित किया। लोगों को स्वदेशी स्वीकार, विदेशी बहिष्कार, देश होगा समृद्ध, बढ़ेगा रोजगार, राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा पखवाड़े के पंपलेट बांटे गए। ...

the pioneer

SJM CALLS FOR BOYCOTT OF CHINESE GOODS

Friday, 15 September 2017 | PNS | BOKARO | in Ranchi

The Bokaro-Dhanbad district unit of Swadeshi Jagran Manch has called for the boycott of Chinese consumer goods and launched a Jan Jagran Abhiyan at Bokaro Steel City on Thursday.

Giving a clarion call to boycott the Chinese goods, Vivekanand Jha the organiser of the Jan Jagran Abhiyan said, "Employment, economy, environment and security are being affected due to increased use of goods manufactured in China. He also said that common citizens should realise this to ultimately make it true and successful. We have a war-like situation at multiple places in areas where we share border with China. "So it is one of the reasons that we should stop buying Chinese goods", he added.

China is earning money as Indians are buying their products. Since we are buying Chinese goods, China has become a strong nation," said Sujit Kumar COC of the Manch. "China is supporting Pakistan in our fight against terrorism. It is, therefore, necessary to boycott Chinese products", he added. ....

Business Standard

Press Trust of India | New Delhi, September 7, 2017

SJM to organise rally for boycott of Chinese goods

The RSS' economic wing Swadeshi Jagran Manch (SJM) will organise a mega rally next month to conclude its campaign for boycott of Chinese goods.

"China is responding to India's principle of Panchs-

heel by adopting a policy to cripple our economic, environment, employment and humanity fabric," SJM's all-India organiser Kashmiri Lal said here.

The Sangh affiliate said it had launched Rashtriya Swadeshi Suraksha Abhiyan earlier this year to make people aware of China's "nefarious designs". ....

ThePrint

23 September, 2017

Swadeshi Jagran Manch film at Ramlilas to show India becoming a Chinese 'colony'

RSS-affiliate SJM ties up with 50 Ramlila committees in Delhi to show the film, which criticises the Narendra Modi government's economic policies.

The Swadeshi Jagran Manch (SJM) has decided to attack China through a provocative short film to be aired at Ramlilas. The film warns viewers that India is becoming a Chinese 'colony'.

The RSS-affiliated economic body intends to tie up with 50 Ramlila committees across Delhi to screen the three-minute film through the festive period. It has already received the assent of 26 committees to screen the film.

The film is critical of the Narendra Modi government when it comes to dealing with what it says is a Chinese economic onslaught. It says given the way things are going, India is well on its way to becoming a colony yet again. .....

FINANCIAL EXPRESS

July 4, 2017

Boycott Chinese products campaign gains fresh momentum: Here's how and why RSS plans to do so amid Sikkim standoff

Amidst the ongoing standoff between Indian and Chinese soldiers in the Doklam area of Sikkim sector, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has planned to step up the 'Boycott Chinese Products' campaign from August 1. According to RSS mouthpiece, Organiser, the RSS would launch a nation-wide mass awareness drive against Chinese goods between August 1 to 15. Apart from this, a country-wide campaign by RSS-affiliated Swadeshi Jagaran Manch (SJM) is already on. SJM claims that the campaign has received the support from people in "good number" and it would conclude on October 29 at Delhi's Ramlila Ground with a massive rally.

In an interview to the Organiser, SJM national vice-president Satish Kumar said around 87 lakh people across the country have pledged to boycott Chinese goods and the campaign is gaining momentum.

Revealing how the SJM is taking up the campaign, Kumar said people supporting the campaign have demonstrated outside the Chinese Embassy, mass protests in many parts of the country have been held and some market associations have also vowed not to import and sell Chinese goods. .....

दैनिक जागरण

September 24, 2017

स्वदेशी जागरण मंच ने 29 की महारैली की तैयारियां पर की चर्चा

संवाद सहयोगीः गुरदासपुरः स्वदेशी जागरण मंच का जिला सम्मेलन स्थानीय होटल में आयोजित किया गया। इसमें उत्तर भारत के संगठक सतीश व राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान पंजाब के प्रमुख चंद्र शेखर विशेष तौर पर उपस्थित हुए।

29 अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में चीन के खिलाफ आयोजित की जा रही महारैली की तैयारियां की रुपरेखा के बारे में सभी कार्यकर्ताओं से बात की और इस रैली में कैसे जाना है, संबंधी विचार किया गया। सतीश ने कहा कि चीन ने भारत के खिलाफ व्यापार की जंग छेड़ रखी है। चीन का मुख्य हथियार है सामान को सस्ता बेचना और भारत के व्यापार को तबाह करना। जिसे लोग समझ नहीं पा रहे है। इस लिए हमें लोगों को जागरुक करना है और चीनी सामान का बहिष्कार करना है।

August 8, 2017

रैली निकालकर किया चीनी वस्तुओं का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्लीः कोटला विहार विकास मंच की ओर से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान चीनी सामान को जलाया गया। रैली में लोगों ने चीन में निर्मित वस्तुओं को नहीं खरीदने की अपील की, साथ ही दुकानदारों से कहा कि आप चीन में निर्मित वस्तुओं को नहीं बेचें।

संस्था पदाधिकारी विनोद शर्मा ने कहा कि भारतीय बाजार में धीरे–धीरे चीन में निर्मित वस्तुएं अपनी पैठ बना रही हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। हमें स्वदेशी सामानों के उपयोग पर बल देना चाहिए। अगर हम स्वदेशी सामान की खरीदारी करेंगे तो देश में रोजगार बढ़ेगा और हम सभी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संस्था के पदाधिकारी घर–घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों पर इसका सकारात्मक असर हो रहा है। .... ❑❑

छोटे निर्यातकों को जीएसटी में बड़ी राहत

जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल की इस बैठक से छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिल गया है। काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेने की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। पहले यह सीमा 75 लाख रुपए प्रस्तावित थी। इस स्कीम के तहत कारोबारियों को सिर्फ 2 फीसद का टैक्स चुकाना होता है। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद GSTR–1, GSTR–2 और GSTR–3 फॉर्म हर महीने भरना होता था, लेकिन अब आपको ये ही तीनों फॉर्म तिमाही आधार पर भरने होंगे। यह एक बड़ी राहत है। हालांकि आपको टैक्स का भुगतान हर महीने करना होगा। यह छोटे कारोबारियों के लिए ही है जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपए का है।

केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है। सरकार

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना लगभग तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपये करने का फैसला किया गया था। अगर एनएसी की मीटिंग में सबकुछ ठीक रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। हालांकि यह कर्मचारियों द्वारा की जारी 26,000 की मांग से कम होगा लेकिन 21,000 रुपये होने पर भी कर्मचारियों को फायदा ही होगा।

50 फीसदी कृषि कर्ज 5 राज्यों के किसानों पर

किसानों की घटती इनकम और उन पर बढ़ता कर्ज का बोझ पूरी इकोनॉमी के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। कर्ज के बोझ का असर देश के 5 राज्यों के किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट "एग्रीकल्चर लोन बुक अकाउंट्स" के अनुसार साल 2015–16 तक बैंकों द्वारा कुल 8.94 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। जिसमें से करीब 50 फीसदी लोन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा लिए गए हैं।

राज्य कुल लोन में हिस्सेदारी

(फीसदी में)

तमिलनाडु	11.4	उत्तर प्रदेश	11.3
महाराष्ट्र	9.0	पंजाब	8.7
आंध्र प्रदेश	8.5		

रिपोर्ट के अनुसार करीब एग्री लोन का 40 फीसदी बोझ छोटे और सीमांत किसानों पर है। जिन पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक कर्ज है। बैंकों ने साल 2015–16 तक कुल 3.57 लाख करोड़ रुपए का लोन छोटे और सीमांत किसानों को दिया है। किसान करीब 6 लाख करोड़ का लोन फसल के लिए लेते हैं। जबकि 3 करोड़ रुपए का लोन कृषि से जुड़ी दूसरी गतिविधियों और इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है।

हाल ही में जो कर्ज माफी की घोषणाएं की गई हैं। उसका बोझ भी इन राज्यों की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इस बात का भी जिक्र आरबीआई की रिपोर्ट में किया गया है।

राज्य	*माफ एग्री लोन की राशि*
उत्तर प्रदेश	36000 करोड़
महाराष्ट्र	34000 करोड़
पंजाब	10000 करोड़
कर्नाटक	8000 करोड़

सरकार सस्ती दर पर बेचेगी दाल

दालों के बफर स्टॉक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सस्ती दर पर दाल देगी। केंद्र ने सभी राज्यों को सस्ती कीमत पर दाल खरीदने का प्रस्ताव दिया है, पर सिर्फ चार राज्यों ने ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में सरकार केंद्र की योजनाओं में दाल मुहैया कराने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट जल्द इस बारे में फैसला कर सकती है।

सरकार 5.5 लाख टन दाल राज्य और केंद्रीय योजनाओं में देगी। तेलंगाना,

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक को सस्ती दर पर 3.5 लाख टन दाल दी गई है। इसके साथ करीब दो लाख टन दाल मिड डे मील सहित केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लिए दी जा सकती है। इसके साथ नीलामी के जरिए कुछ दाल को खुले बाजार में भी बेचा गया है।

नौकरियों का बुरा हाल

वित्त वर्ष 2016–17 में ज्यादातर कंपनियों में पिछले सालों की तुलना में नौकरियां कम हुई हैं। कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के 742,012 की तुलना में वित्त वर्ष 2016–17 में केवल 730,694 नौकरियां दीं। रोजगार में 11,318 की ये कमी धातु, ऊर्जा, कैपिटल गुड्स, निर्माण क्षेत्र और एमएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों में हुई है। 107 कंपनियों में मार्च 2015 तक कुल 684,452 कर्मचारी थे जिनकी संख्या मार्च 2016 में घटकर 677,296 रह गयी और मार्च 2017 तक ये संख्या घटकर 669,784 हो गयी। नौकरी में कमी की संख्या छोटी लग सकती है लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये एक प्रवृत्ति को दिखाती है जो चिंता का विषय है। देश की सबसे बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों में कमी से इन कंपनियों के विस्तार की योजनाओं और निकटवर्ती विकास की उम्मीदों का पता चलता है।

27 वस्तुओं पर घटी जीएसटी दरें

6 अक्टूबर 2017 को वित्तमंत्री अरूण जैटली की अध्यक्षता में जीएसटी

(गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की 22वीं बैठक में टैक्स की दरों को घटाया गया–

- कपड़ा व्यापारियों को मैनमेड यार्न पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी।
- डीजल इंजन और पंप के पुर्जों पर 28 से घटाकर 18 फीसदी।
- क्लिप और पिन जैसे स्टेशनरी वस्तुओं पर 28 से 18 फीसदी।
- अनब्रैंडेड आयुर्वेदिक दवाओं पर 12 से पांच फीसदी।
- ई–वेस्ट पर 28 से घटाकर 5 फीसदी।
- खाखड़ा व प्लेन चपाती पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी।
- बच्चों के पैकेज्ड फूड पर 12 प्रतिशत से 5 फीसदी।
- मार्बल और ग्रेनाइट को छोड़कर दूसरे स्टोन, स्टेशनरी पर जीएसटी 28 से 18 फीसदी।
- अनब्रैंडेड नमकीन पर 12 से 5 फीसदी।
- प्लास्टिक, रबर वेस्ट पर जीएसटी 18 से 5 फीसदी, पेपर वेस्ट पर 12 से 5 फीसदी।
- जरी के काम और आर्टिफिशल जूलरी पर जीएसटी 12 से 5 फीसदी।
- कटे हुए आम पर जीएसटी 12 से 5 फीसदी।
- जॉब वर्क करने वालों के लिए जीएसटी की दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई।

21 से घटकर 10–15 हो सकते है सरकारी बैंक

देश में सरकारी बैंकों की संख्या 21 से घटकर 10 से 15 पर लाई जा सकती है। हालांकि, इनमें सरकार की

बहुलांश हिस्सेदारी बनी रहेगी। अभी 21–22 सरकारी बैंक हैं। एकीकरण के बाद इन बैंकों की संख्या घटकर 10 से 15 रह जाएगी। एकीकरण की ताजा प्रक्रिया के तहत भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) और पांच सहयोगी बैंकों का 1 अप्रैल, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया है। इससे एसबीआई दुनिया के 50 शीर्ष बैंकों में शामिल हो गया है।

पांच श्रेणियों में बंटेंगी म्यूचुअल फंड योजनाएं

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को श्रेणीबद्ध करने के लिए नए नियम जारी किए है। सेबी ने योजनाओं को पांच श्रेणियों में बांटने का निर्देश दिया है। ऐसा होने से एक जैसी म्यूचुअल फंड योजनाओं को पहचानना आसान होगा। सेबी ने सकरुलर जारी कर सभी म्यूचुअल फंडों को अपनी योजनाओं को इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अन्य के नाम से कुल पांच श्रेणियों में बांटने के लिए कहा है। म्यूचुअल फंडों को निर्देश दिया गया है कि उनकी नई योजनाएं किसी पुरानी योजना की नकल नहीं होनी चाहिए।

इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड्स, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड के अलावा बाकी फंडों को एक श्रेणी में केवल एक योजना चलाने की अनुमति दी जाएगी। म्यूचुअल फंडों को अपनी सभी योजनाओं का विश्लेषण करते हुए निर्धारित श्रेणियों में विभक्त करना होगा और जल्द से जल्द प्रस्ताव सेबी के पास जमा कराना होगा। इसके लिए म्यूचुअल फंडों को अधिकतम दो महीने का समय दिया गया है। इसके बाद योजनाओं में जरूरी बदलावों के लिए उन्हें अधिकतम तीन महीने का समय मिलेगा।

मुकेश अंबानी भारतीय अमीरों में शीर्ष पर

भारत के मुकेश अंबानी फोर्ब्स की ताजा लिस्ट में अमीर भारतीयों की लिस्ट में पहले स्थान पर बरकरार है। अंबानी इस लिस्ट में लगातार 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर उभरे हैं। उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 38 अरब डॉलर पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि आर्थिक सुस्ती के बाद भी शीर्ष 100 अमीर लोगों की संपत्ति में 26 प्रतिशत इजाफा हुआ है।

देश की तीसरी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी 19 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। उन्होंने पिछले साल की तुलना में दो स्थान की छलांग लगाई है। हिंदुजा ब्रदर्स 18.4 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, लक्ष्मी मित्तल 16.5 अरब डॉलर के साथ चौथे तथा पल्लोनजी मिस्त्री 16 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर रहे हैं।

दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मा के दिलीप सांवी 12.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ नौवें स्थान पर रहे हैं। वह पिछले साल की सूची में दूसरे स्थान पर थे।

फॉर्ब्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक प्रयोगों का भारत के अरबपतियों पर नाममात्र का असर पड़ा है। पिछले एक साल के दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति में 153 अरब डॉलर यानी 67 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस तरह वह शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही एशिया के शीर्ष पांच अमीरों में शामिल होने में सफल रहे हैं। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी अमीरों की सूची में काफी नीचे 45वें स्थान पर रहे हैं। उनकी संपत्ति 3.15 अरब डॉलर आंकी गयी है। पिछले साल वह 32वें तथा 2015 में 29वें स्थान पर रहे थे।

भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनोमी होगाः एचएसबीसी

भले ही कुछ सुधारों के कारण देश की जीडीपी वृद्धि दर प्रभावित हुई हो लेकिन मध्यम अवधि में संभावना उत्साहजनक दिखायी देती है। वृद्धि प्रवृत्ति को देखते हुए भारत अगले दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट में कहा, ''हालांकि आज वैश्विक जीडीपी का केवल 3 प्रतिशत है, लेकिन भारत की वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने से लगता है कि यह अगले दशक में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।'' एचएसबीसी का मानना है कि भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत रहेगी जो पिछले वित्त

वर्ष 2016–17 के 7.1 प्रतिशत के मुकाबले कम है। वहीं 2018–19 में इसके 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं 2019–20 में यह बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.7 प्रतिशत पर आ गयी जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है। इसका मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र में नरमी के बीच नोटबंदी का प्रभाव है। एचएसबीसी का मानना है कि 2019–20 के बाद मौजूदा सुधारों के कारण उत्पन्न अल्पकालीन बाधाएं दूर हो जाएंगी।

दवा के असली दाम जान सकेंगे उपभोक्ता

दवा के पैकेटों पर जल्द ही अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ फैक्ट्री में बनने में आई लागत भी लिखी होगी। इससे उपभोक्ताओं को पता चलेगा कि दवा का असली दाम क्या है और कंपनियां उस पर कितना मुनाफा कमा रही हैं। सरकार का मानना है कि इससे दवा बाजार में पारदर्शिता आएगी। मनमाने दाम वसूलने की जगह दवा कंपनियों पर दाम कम रखने का दबाव भी बढ़ेगा। अगर दवा विदेश से आयात की गई है तो उस पर लैंडेड प्राइस यानी भारत आने के वक्त की

कीमत लिखी होगी। समझा जाता है कि केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के नियम 96 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद सभी दवा निर्माताओं के लिए यह जानकारी पैकेटों पर लिखना अनिवार्य हो जाएगा।

नियम 96 के अनुसार, फिलहाल कंपनियों को पैकेट पर सभी करों सहित एमआरपी लिखनी होती है। इसके अलावा दवा निर्माता कंपनी का नाम, स्थान, दवा का नाम, तारीख, बैच नंबर, वजन, मात्रा आदि ही लिखना होता है। दवा के फार्मूले में मिलाए गए तत्वों की जानकारी भी देनी होती है। लेकिन उत्पादन लागत का उल्लेख नहीं होता।

फीफा विश्व कप 2017

देश की राजधानी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को फीफा अंडर–17 विश्व कप के आगाज के साथ इतिहास रचा गया और इस पल के साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। भारत को पहली बार किसी फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने का गौरव मिला है। फुटबॉल विश्व कप के 87 साल के इतिहास में पहली बार भारत का नाम अंकित हुआ। 1930 में उरुग्वे में पहला फीफा विश्व कप और 1985 में चीन में पहला अंडर–17 विश्व कप हुआ था, लेकिन भारत 6 अक्टूबर 2017 से इससे दूर था।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति से देश में फुटबाल को और अधिक प्रोत्साहन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। फुटबाल को लेकर एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही खासा ध्यान रहा है। खिलाड़ियों के लिए देश भर में सघन खोज अभियान से लेकर उन्हें मैदान तक ले जाने का प्रयास धीरे–धीरे परवान चढ़ रहा है।

बंगलूरु एयरपोर्ट पर होगी आधार से एंट्री

बंगलूरु देश का पहला एयरपोर्ट होगा, जहां एयरपोर्ट पर जल्द ही आधार कार्ड के जरिए यात्रियों की एंट्री होगी और बोर्डिंग पास भी इसी से मिलने लगेगा। इससे उन्हें किसी और डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार बेस्ड सिस्टम से यात्रियों की एंट्री से लेकर के बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में केवल 10 मिनट का समय लगेगा। अभी इस प्रोसेस को पूरा करने में आधा घंटे से ऊपर का समय लगता है।

24 घंटे बिजली देने के लिए 'सौभाग्य' स्कीम

पूरे देश में 24 घंटे बिजली देने के लिए केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 'सौभाग्य' स्कीम ला रही है। केंद्र सरकार राज्यों के बिजली बोर्ड को ट्रांसफार्मर, मीटर, तार जैसे उपकरण लगाने पर सब्सिडी देगी। इस सब्सिडी को देने से केंद्र के ऊपर 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा आएगा। सरकार हर गांवों में 2019 तक सातों दिन, 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहती है।

केंद्र सरकार ने दो साल पहले पावर फॉर ऑल स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था। अब इस स्कीम में कुछ बदलाव किया जाएगा और नया टारगेट बनाने की घोषणा की जाएगी। पावर मिनिस्ट्री का दावा है कि केवल 3046 गैर आबादी वाले गांवों को छोड़कर सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है।

टाटा टेलीसर्विसेज में बड़ी छंटनी

टाटा समूह की बड़ी कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज अपने 5000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए "एग्जिट प्लान" (निकालने की योजना) बना रही है। इस योजना में 3 से 6 महीने तक नोटिस पीरियड का प्रावधान रखा जा सकता है। जो लोग इस नोटिस पीरियड से पहले छोड़ना चाहेंगे उन्हें अलग से भत्ता दिया जाएगा। वरिष्ठ कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लायी जाएगी और कुछ कर्मचारियों को समूह की दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

टाटा टेलीसर्विसेज पर काफी कर्ज है और कंपनी जल्द बंद होने वाली है।

कंपनी ने अपने सभी सर्किल हेड को 31 मार्च 2018 तक नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। टाटा समूह की दूसरी कंपनियों के ऊपर भी बंदी की तलवार लटक रही है। मुनाफा कमा रही टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस को छोड़कर बाकी कंपनियों पर करीब 25.5 अरब डॉलर का कर्ज है।

सुपरफास्ट ट्रेनों में डिस्पेंसर सीट कवर

देश भर में चल रही तमाम सुपरफास्ट ट्रेनों के टॉयलेट में लगे कमोड में अब बटन दबाते ही बैठने वाले स्थान पर कवर आ जाएगा। यह संभव होगा ऑटो डिस्पेंसर सीट कवर से। रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रयोग के तौर ऑटो डिस्पेंसर पश्चिम रेलवे द्वारा एक राजधानी एक्सप्रेस में लगाया गया था। यात्रियों से मिले बढ़िया रिस्पांस के बाद रेलवे अब तमाम सुपर फास्ट ट्रेनों के फर्स्ट एसी कोच के टॉयलेट में लगे कमोड में ऑटो डिस्पेंसर सीट कवर लगवाने जा रहा है। इसके तहत कमोड के ऊपर एक बटन लगा हुआ था। उसे दबाने के बाद उसमें से एक पेपर निकलता था जो कमोड के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। प्रयोग करने के बाद बटन दबाने के बाद वह पेपर फ्लश के माध्यम से नीचे चला जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा पेपर कमोड पर बैठने वाले स्थान पर आ जाता है।

उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज एक्सप्रेस, इलाहाबाद–नई दिल्ली दुरंतो और इलाहाबाद–जयपुर एक्सप्रेस में इसे लगाने की तैयारी है।

आर्मको ने खोला भारत में आफिस

दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी साउदी अरब की आर्मको ने भारत में कच्चे तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए गुरूग्राम में अपना आफिस खोला। साउदी अरब कुछ माह पहले तक भारत का कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में एक नंबर पर था, लेकिन अब यह स्थान इराक ने ले लिया है।

साउदी अरब इराक के बाद भारत के लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत में 19 प्रतिशत कच्चा तेल और 29 प्रतिशत एलपीजी आयात साउदी अरब से होता है। वर्ष 2016–17 के दौरान भारत ने साउदी अरब से 3.95 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया।

अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण बंद

पीएसयू, बीमा कंपनियों और सरकारी बैंकों के अधिकारियों के बच्चे अब ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसी कंपनियों–संस्थाओं में अब नीचे के स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ

मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी पदों के साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों में पदों की समतुल्यता तथा ओबीसी के आरक्षण लाभ दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय नौकरियों की तरह पीएसयू में भी निचली श्रेणी में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से 8 लाख बढ़ाने का लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव बीते 24 साल से लंबित था।

यमन जाने पर प्रतिबंध

भारत सरकार ने नागरिकों के लिए यमन की यात्रा पर रोक लगा दी है। केरल के अपहृत कैथोलिक पादरी टॉम के सकुशल भारत वापस लौटने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। टॉम को 4 मार्च, 2016 को एक आतंकी हमले में अगवा कर लिया गया था। उन्हें 12 सितंबर, 2017 को आईएस के चंगुल से छुड़ाकर ओमान लाया गया था। सरकार ने कहा है, "जनहित में ऐसा करना जरूरी है, इसलिए यह निर्देश दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज यमन की यात्रा के लिए अवैध है क्योंकि यमन की यात्रा से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोई भी भारतीय नागरिक जो इस नोटिफिकेशन की अवहेलना कर यमन की यात्रा करता है, उसपर कार्रवाई की जाएगी।"

अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यमन की यात्रा पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है, इसके अलावा वहां से अमेरिका आने पर भी पाबंदी है। दो साल से ज्यादा समय से छिड़े यमन के गृह युद्ध में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं, जिनमें अधिकांश नागरिक हैं और तीस लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। ❑❑